



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2016/माघ 26, 1937

No. 100]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2016/ MAGHA 26, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 15 फरवरी, 2016

सं.फेमा. 361/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.नि.165 (अ).- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में,

ए. विनियम 2 में, खंड (viiए) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(viiए) अनिवासी भारतीय (NRI) का तात्पर्य भारत से बाहर के निवासी उम्म व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक है अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(ए) के अर्थों में "ओवरसीज़ भारतीय नागरिक" का कार्ड होल्डर है।"

बी. विनियम 5(3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(i) कोई अनिवासी भारतीय (NRI) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत, प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज से प्रतिभूतियां अथवा यूनिटें अर्जित कर सकता है।

(ii) कोई अनिवासी भारतीय (NRI) अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, प्रतिभूतियां अथवा यूनिटें अर्जित कर सकता है।

सी. अनुसूची 3, निम्नवत प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्

"अनुसूची – 3

[विनियम 5(3)(i) देखें]

किसी अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय

आधार पर भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज से प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों का अर्जन

1. कोई अनिवासी भारतीय (NRI), प्रत्यावर्तनीय आधार पर, किसी भारतीय कंपनी के शेयर, परिवर्तनीय अधिमानी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर और वारंट अथवा किसी निवेश संस्था (investment vehicle) की यूनिटें किसी स्टॉक एक्सचेंज से निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत खरीद अथवा बेच सकता है:

ए. अनिवासी भारतीय (NRI) किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा एतदर्थ नामित शाखा के जरिए पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत शेयर/परिवर्तनीय अधिमानी शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर/वारंट एवं यूनिटों की खरीद एवं बेच सकते हैं;

बी. किसी एक अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा किसी भारतीय कंपनी के खरीदे गए शेयरों का प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

सी. किसी एक अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी श्रृंखला के अंतर्गत खरीदे गए परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी संबंधित श्रृंखला के परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रदत्त मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

डी. किसी एक अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी श्रृंखला के अंतर्गत खरीदे गए वारंटों का प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी संबंधित श्रृंखला के वारंटों के प्रदत्त मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

ई. सभी अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी कंपनी के खरीदे गए शेयरों का समग्र प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और सभी अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा प्रत्येक श्रृंखला के अंतर्गत खरीदे गए परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा वारंटों का समग्र प्रदत्त मूल्य संबंधित श्रृंखलाओं के परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा वारंटों के प्रदत्त मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

बशर्ते कि, इस खंड में संदर्भित दस प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा को बढ़ाकर चौबीस प्रतिशत किया जा सकता है यदि संबंधित भारतीय कंपनी की सामान्य निकाय की बैठक द्वारा इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया जाए;

एफ. अनिवासी निवेशक खरीदे गए शेयरों/परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ वारंटों एवं यूनिटों की सुपुर्दग्दी लें एवं उन्हें बेचने पर सुपुर्दग्दी दें;

जी. जहां कहीं लागू हो, ये निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति एवं इन विनियमों की अनुसूची 1 के उपबंधों के अधीन सेक्टोरल कैप के अधीन होंगे।

स्पष्टीकरण: "निवेश संस्थाओं" एवं "यूनिटों" के तात्पर्य वही होंगे जैसे कि इन विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (iiजी) और (xiए) में यथा परिभाषित हैं।

2. रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट भेजना

पैराग्राफ 1 में यथा संदर्भित प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा द्वारा इस अनुसूची के अंतर्गत किए गए लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से उसे रिपोर्ट किया जाएगा।

3. अनिवासी भारतीय द्वारा शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/यूनिटों आदि की खरीद और बिक्री के लिए लेनदेन हेतु खाते रखना

इस योजना के तहत निवेश करने के लिए कोई अनिवासी भारतीय, इस अनुसूची के अंतर्गत शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/वारंटों/यूनिटों की बिक्री एवं खरीद संबंधी लेनदेनों की प्राप्ति एवं भुगतान हेतु, पैराग्राफ 1 में संदर्भित प्राधिकृत व्यापारी (विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा) की नामित शाखा में 'नामित एनआरई' खाता खोल सकता है। नामित खाता एनआरई (पीआईएस) खाता कहलाएगा।

नामित शाखा यह सुनिश्चित करेगी कि पोर्टफोलियो निवेश योजना से भिन्न तरीके से अर्जित प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों, जैसे एडीआर / जीडीआर में/के परिवर्तन पर अर्जित अंतर्निहित शेयरों / प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अर्जित शेयरों / परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों / वारंटों अथवा भारत से बाहर अनिवासी भारतीयों से खरीदे अथवा निवासियों / अनिवासियों से निजी व्यवस्था के अंतर्गत अर्जित अथवा भारत में निवास के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियों की बिक्रीगत आगम राशि एनआरई (पीआईएस) खाते में न तो जमा की जाएगी और न ही तत्संबंध में नामे की जाएगी।

4. एनआरई (NRE) (पीआईएस) खाते में अनुमत जमा से अनुमत नामे

जमा

ए. सामान्य बैंकिंग चैनल से विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण;

बी. किसी अनिवासी द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे अन्य एनआरई (NRE) अथवा एफसीएनआर (FCNR) (बी) खाते से अंतरण;

सी. प्रत्यावर्तनीय आधार पर योजना के अंतर्गत शेयरों / परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / वारंटों / यूनिटों के किए गए अर्जन और किसी पंजीकृत दलाल के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में की गई बिक्री (लागू करों के भुगतान के बाद) की निवल आगम राशि; और

डी. प्रत्यावर्तनीय आधार पर योजना के अंतर्गत किए गए निवेश पर अर्जित लाभांश अथवा आय।

नामे

ए. अर्जित लाभांश अथवा आय के आवक विप्रेषण;

बी. योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयरों / परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / वारंटों / यूनिटों की किसी पंजीकृत दलाल के जरिए स्टॉक एक्सचेंज से की गई खरीद के लिए आदयगी;

सी. योजना के अंतर्गत प्रतिभूतियों/यूनिटों की बिक्री/खरीद के कारण प्रभारों हेतु।

डी. भारत से बाहर विप्रेषण अथवा किसी अनिवासी भारतीय अथवा ऐसा खाता रखने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति के खाते से एनआरई (NRE) अथवा एफसीएनआर (FCNR) (बी) खाते में अंतरण।

5. छूट

मौजूदा एनआरओ (पीआईएस) खातों को एनआरओ खाते के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा।"

डी. अनुसूची 4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, भर्ता

" अनुसूची - 4

[विनियम 5(3)(ii) देखें]

किसी अनिवासी भारतीय द्वारा, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों का वर्जन

खरीद के लिए अनुमति

1. भारत से बाहर निगमित कंपनी, ट्रस्ट और भागीदारी फर्म, जो अनिवासी भारतीय द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित हैं, सहित कोई अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्किटी शेरर, परिवर्तनीय अधिमानी शेरर, परिवर्तनीय डिवेंचर, वारंट अथवा यूनिटें अर्जित एवं धारित कर सकता है, जिन्हें किसी निवासी द्वारा किए गए निवेश के समतुल्य घरेलू निवेश माना जाएगा। सामान्य स्वरूप को खोए बिना, यह उल्लेख किया जाता है कि -

- ए. कोई अनिवासी भारतीय बिना किसी सीमा के किसी स्टॉक एक्स्चेंज अथवा उससे बाहर किसी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों की खरीद अप्रत्यावर्तनीय आधार पर कर सकता है।
- बी. कोई अनिवासी भारतीय बिना किसी सीमा के किसी स्टॉक एक्स्चेंज अथवा उससे बाहर किसी निवेश संस्था द्वारा जारी यूनिटों की खरीद अप्रत्यावर्तनीय आधार पर कर सकता है।
- सी. कोई अनिवासी भारतीय किसी भागीदारी फर्म अथवा मालिकाना फर्म अथवा सीमित देयता भागीदारी फर्म की पूँजी में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अंशदान कर सकता है।

स्पष्टीकरण: "निवेश संस्थाओं" एवं "यूनिटों" के तात्पर्य वही होंगे जैसेकि इन विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (ii)जी) और (xi)ए) में यथा परिभाषित हैं।

खरीद पर प्रतिबंध

2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, कोई अनिवासी भारतीय, इस अनुसूची के अंतर्गत, किसी निधि कंपनी अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट कारोबार अथवा फार्म हाउस के निर्माण अथवा हस्तांतरणीय विकास अधिकार में संलग्न कंपनियों के इक्किटी शेररों, परिवर्तनीय अधिमानी शेररों, परिवर्तनीय डिवेंचरों, वारंटों अथवा यूनिटों में निवेश नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, "रियल इस्टेट कारोबार" का तात्पर्य लाभ कमाने के दृष्टिकोण से भूमि एवं अचल संपत्ति के ऐसे सौदे करना है और उसमें टाउनशिप का विकास, आवासीय, वाणिज्यिक परिसरों, सड़क अथवा पुलों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप के निर्माण शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, संपत्ति के लीज़ से प्राप्त किराए से हुई आमदनी, जो अंतरणीय नहीं है, को रियल इस्टेट कारोबार की राशि नहीं माना जाएगा। सेबी (REITs) विनियमावली, 2014 के तहत पंजीकृत एवं विनियमित किसी 'निवेश संस्था (investment vehicle)' की यूनिटों में किया गया निवेश भी "रियल इस्टेट कारोबार" की परिभाषा से बाहर होगा।"

खरीद के लिए भुगतान का तरीका

3. इस अनुसूची के अंतर्गत निवेश करने के लिए प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए विप्रेषण से अथवा भारत में किसी बैंक के पास रखे एनआरई / एफसीएनआर / एनआरओ (NRE/FCNR/NRO) खाते में जमा निधियों से अदा की जा सकती है।

बिक्री / परिपक्षतागत आगम राशि

4. इस अनुसूची के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों की बिक्री/परिपक्षतागत आगम राशि (लागू करने को घटाकर) केवल एनआरओ (NRO) खाते में जमा की जाएगी, भले ही प्रतिफल राशि का भुगतान किसी भी स्वरूप के खाते से किया गया हो।
5. इस योजना के अंतर्गत किए गए निवेश की राशि और उसकी पूँजी में हुई वृद्धि भारत से बाहर प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकेगी।"

[सं. 1/1/ईएम-2016]

बी.पी.कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली **8 मई 2000** को सा.का.नि. सं.406 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 4 (अ) दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003	सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004	सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004	सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004	सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004	सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005	सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005	सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006	सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006	सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007	सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008	सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008	सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009	सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010	सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012	सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012	सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012	सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012	सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013	
सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013	
सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013	

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 15th February , 2016

No.FEMA.361/2016-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2016

G.S.R. 165 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulation

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000),

A. In Regulation 2, the existing clause (viiia) shall be substituted, namely:

“(viiia) Non-Resident Indian (NRI) means an individual resident outside India who is citizen of India or is an ‘Overseas Citizen of India’ cardholder within the meaning of section 7 (A) of the Citizenship Act, 1955.”

B. Regulation 5 (3) shall be substituted, namely

“(i) A Non- Resident Indian (NRI) may acquire securities or units on a Stock Exchange in India on repatriation basis under the Portfolio Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 3.

(ii) A Non- Resident Indian (NRI) may acquire securities or units on a non-repatriation basis, subject to the terms and conditions specified in Schedule 4.

C. Schedule 3 shall be substituted, namely

“Schedule-3

[See Regulation 5(3) (i)]

Acquisition of Securities or Units by

a Non-Resident Indian (NRI) on a Stock Exchange in India on Repatriation basis under the Portfolio Investment Scheme

1. A Non-resident Indian (NRI) may purchase or sell shares, convertible preference shares, convertible debentures and warrants of an Indian company or units of an investment vehicle, on repatriation basis, on a recognised stock exchange, subject to the following conditions:

- a. NRIs may purchase and sell shares /convertible preference shares/ convertible debentures /warrants and units under the Portfolio Investment Scheme through a branch designated by an Authorised Dealer for the purpose;
- b. The paid-up value of shares of an Indian company purchased by any individual NRI should not exceed five percent of the paid-up value of shares issued by the company concerned;
- c. the paid-up value of convertible preference shares or convertible debentures of any series purchased by any individual NRI on repatriation basis should not exceed five percent of the paid-up value of convertible preference shares or convertible debentures of that series issued by the company concerned;
- d. the paid-up value of warrants of any series purchased by any individual NRI on repatriation basis should not exceed five percent of the paid-up value of warrants of that series issued by the company concerned;

- e. the aggregate paid-up value of shares of any company purchased by all NRIs on repatriation basis should not exceed ten percent of the paid-up value of shares of the company and the aggregate paid-up value of each series of convertible preference shares or convertible debentures or warrants purchased by all NRIs should not exceed ten percent of the paid-up value of that series of convertible preference shares or convertible debentures or warrants;

Provided that the aggregate ceiling of ten per cent referred to in this clause may be raised to twenty-four per cent if a special resolution to that effect is passed by the General Body of the Indian company concerned;

- f. The NRI investor should take delivery of the shares/convertible preference shares/ convertible debentures /warrants and units purchased and give delivery of the same when sold;
- g. The investment shall be subject to the provisions of the FDI policy and Schedule 1 of these Regulations in respect of sectoral caps wherever applicable.

Explanation: 'Investment Vehicles' and 'Units' and shall have the same meaning as defined in sub-regulation (ii g) and (xi A) of Regulation 2 of these Regulations.

2. Report to Reserve Bank

The reporting of transactions under this Schedule shall be made by the designated branch of the Authorised Dealer referred to in paragraph 1, in a manner specified by Reserve Bank of India.

3. Maintenance of accounts by an NRI for routing transactions for purchase and sale of shares / convertible debentures/ units, etc.

An NRI may open a designated NRE account (opened and maintained by Authorised Dealer bank in terms of the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000) for the purpose of investment under this scheme with a designated branch of an Authorized Dealer bank referred to in paragraph 1, for routing the receipt and payment for transactions relating to sale and purchase of shares /convertible preference shares/ convertible debentures/ warrants/ units under this Schedule. The designated account will be called an NRE (PIS) Account.

The designated branch shall ensure that sale proceeds of securities or units which have been acquired by modes other than Portfolio Investment Scheme such as underlying shares acquired on conversion of ADRs / GDRs, shares / convertible preference shares / convertible debentures /warrants acquired under FDI Scheme or purchased outside India from other NRIs or acquired under private arrangement from residents/non-residents or purchased while resident in India, do not get credited in the NRE (PIS) Account and vice-versa.

4. Permitted Credits/ Debits in NRE(PIS)account Credits

- a. Inward remittances in foreign exchange through normal banking channels;
- b. Transfer from the NRI's other NRE accounts or FCNR (B) accounts maintained with Authorised Dealer in India;
- c. Net sale proceeds (after payment of applicable taxes) of shares / convertible preference shares /convertible debentures /warrants/ units acquired on repatriation basis under the Scheme and sold on stock exchange through registered broker; and
- d. Dividend or income earned on investment made on repatriation basis under the Scheme

Debits

- a. Outward remittances of dividend or income earned;
- b. Amounts paid on account of purchase of shares /convertible preference shares/ convertible debentures / warrants/ units on repatriation basis on stock exchanges through registered broker under the Scheme; and
- c. Any charges on account of sale / purchase of securities or units under the Scheme.
- d. Remittances outside India or transfer to NRE / FCNR (B) accounts of the account holder of the NRI or any other person eligible to maintain such account.

5. Saving

The existing NRO (PIS) accounts may be re-designated as NRO account."

- D. Schedule 4 shall be substituted, namely

“Schedule-4**[See Regulation 5(3) (ii)]****Acquisition of Securities or units by a Non-Resident Indian (NRI), on Non-Repatriation basis****Permission to purchase**

1. A Non-resident Indian (NRI), including a company, a trust and a partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by non-resident Indians, may acquire and hold, on non-repatriation basis, equity shares, convertible preference shares, convertible debenture, warrants or units, which will be deemed to be domestic investment at par with the investment made by residents. Without loss of generality, it is stated that
 - a. An NRI may acquire, on non-repatriation basis, any security issued by a company without any limit either on the stock exchange or outside it.
 - b. An NRI may invest, on non-repartition basis, in units issued by an investment vehicle without any limit, either on the stock exchange or outside it.
 - c. An NRI may contribute, on non-repatriation basis, to the capital of a partnership firm, a proprietary firm or a Limited Liability Partnership without any limit.

Explanation: ‘Investment Vehicles’ and ‘Units’ and ‘shall have the same meaning as defined in sub-regulation (ii g) and (xi A) of Regulation 2 of these Regulations.

Prohibition on purchase

2. Notwithstanding what has been stated in paragraph 1, an NRI shall not make any investment, under this Schedule, in equity shares, convertible preference shares, convertible debenture, warrants or units of a Nidhi company or a company engaged in agricultural/plantation activities or real estate business or construction of farm houses or dealing in Transfer of Development Rights.

Explanation: For the purpose of this paragraph, "Real estate business" means dealing in land and immovable property with a view to earning profit therefrom and does not include development of townships, construction of residential commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships. Further, earning of rent income on lease of the property, not amounting to transfer, will not amount to "real estate business". Investment in units of Real Estate Investment Trusts (REITs) registered and regulated under the SEBI (REITs) regulations 2014 shall also be excluded from the definition of "real estate business".

Method of payment for purchase

3. The consideration for investment under this Schedule shall be paid by way of inward remittance through normal banking channel from abroad or out of funds held in NRE/FCNR/NRO account maintained with a bank in India:

Sale/ Maturity proceeds

4. The sale/maturity proceeds (net of applicable taxes) of the securities or units acquired under this Schedule shall be credited only to NRO account irrespective of the type of account from which the considerations for acquisition were paid.
5. The amount invested under this Scheme and the capital appreciation thereon shall not be allowed to be repatriated abroad.”

[No. 1/1/EM/2016]

B.P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:- The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
 G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003

G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005

G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010	G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013	G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013	G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013	G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013	G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013	G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013	G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013	G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015
G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013	G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015
G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013	G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015
G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013	

अधिसूचना

मुंबई, 15 फरवरी, 2016

सं.केमा. 362/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन)
विनियमावली, 2016

सा.का.नि.166(अ).-विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.केमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में,

(ए) विनियम 2 में खंड (vii A) के पश्चात और मौजूदा खंड (vii a) से पहले निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात :

"(vii AA) "विनिर्माण" शब्द का, उसकी व्याकरणिक विविधता सहित, तात्पर्य उस निर्जीव भौतिक पदार्थ अथवा चीज़ के स्वरूप में परिवर्तन से है, जो (ए) किसी एक पदार्थ अथवा वस्तु अथवा चीज़ से परिवर्तित होकर किसी नए और विशिष्ट पदार्थ अथवा वस्तु अथवा चीज़ के रूप में रूपांतरित हुआ है और जिसका नाम, स्वरूप और उपयोग अलग हो गया है अथवा (बी) किसी विशिष्ट और नए पदार्थ अथवा वस्तु अथवा चीज़ को भिन्न रसायनिक बनावट अथवा अभिन्न संरचना के रूप में बनाया गया हो।"

(बी) विनियम 14 में,

(ए) उप-विनियम 1 में, खंड (i) और खंड (ia) को निम्नवत रूप में संशोधित किया गया है :

"(i) इस विनियम के उद्देश्य से, 'स्वामित्व और नियंत्रण' अभिव्यक्ति का अर्थ निम्न प्रकार है और वह निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करता है

(ए) किसी कंपनी को तभी निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनी समझा जाएगा जब उसके 50% से अधिक पूँजी का लाभप्रद स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों और/अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास हो, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण मूलभूत रूप से निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो। सीमित देयता भागीदारियों (LLP) को तभी निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली सीमित देयता भागीदारी (LLP) माना जाएगा जब उसमें 50% से अधिक निवेश निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाए और / अथवा ऐसी एंटीटी जिनका 'स्वामित्व और नियंत्रण' मूलभूत रूप से निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो और ऐसे निवासी भारतीय नागरिकों और तथा एंटीटियों के पास अधिकांश प्रॉफ़िट शेयर हों।

(बी) कोई कंपनी जिस पर अनिवासियों का स्वामित्व है अर्थात ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है।

(i) ए) "नियंत्रण" में अधिकतम निवेशकों की नियुक्ति का अधिकार शामिल है अथवा शेयर होल्डिंग अथवा प्रबंध अधिकार अथवा शेयरहोल्डर एंट्रीमेंट अथवा बोटिंग एंट्रीमेंट से प्राप्त प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों का नियंत्रण शामिल है।

स्पष्टीकरण : सीमित देयता भागीदारियों (LLP) के प्रयोजन से, 'नियंत्रण' का तात्पर्य अधिकतम नामित भागीदारों की नियुक्ति के अधिकार से है, जहां उक्त सीमित देयता भागीदारी (LLP) की नीतियों पर ऐसे नामित भागीदारों का, अन्य भागीदारों के विशिष्ट अपवर्जन सहित, समग्र नियंत्रण हो।

(बी) उप-विनियम 3 में, खंड (iv) के मौजूदा उप-खंड (डी) को संशोधित किया गया है, अर्थात :

"डी) सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में, जहां सेक्टोरल कैप 49% है, वहाँ कंपनी का 'स्वामित्व और नियंत्रण' निवासी भारतीय नागरिकों के पास तथा भारतीय कंपनियों, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना आवश्यक है।

(ए) इस प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) में यथा परिभाषित लोक वित्त संस्थानों, जैसा भी मामला हों, को छोड़कर सर्वाधिक शेयरधारक भारतीय द्वारा धारित शेयर कुल एंट्रीटी के कम से कम 51% होने चाहिए। इस खंड में उल्लिखित 'सर्वाधिक शेयरधारक भारतीय' में निम्नलिखित में से कोई एक अथवा उनका समूह शामिल है:

(i) किसी एक व्यक्ति के शेयरधारक होने के मामले में,

(एए) व्यक्तिगत शेयरधारक,

(बीबी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में दिये गए अर्थ के दायरे में शामिल शेयरधारक का रिश्तेदार,

(सीसी) कोई कंपनी / कंपनी-समूह से संबन्धित व्यक्तिगत शेयरधारक / हिन्दू अविभक्त परिवार, जिसमें उसके प्रबंध और नियंत्रण हित शामिल हैं।

(ii) भारतीय कंपनी के मामले में,

(एए) कोई भारतीय कंपनी

(बीबी) एक ही प्रबंधन एवं स्वामित्व नियंत्रण के तहत आने वाली भारतीय कंपनियों का समूह

(बी) इस खंड के प्रयोजन के लिए 'भारतीय कंपनी' वह कंपनी होगी, जिसमें निवासी भारतीय अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथा परिभाषित रिश्तेदार / हिन्दू अविभक्त परिवार की एकल अथवा सामूहिक शेयरधारिता कम से कम 51% हो।

(सी) वशर्ते कि उपर्युक्त खंड (i) एवं (ii) में उल्लिखित एक या सभी एंटीटीयों के समूह के मामले में आवेदक कंपनी के मामलों के प्रबंधन हेतु प्रत्येक पार्टी का आपस में विशिक रूप से बाध्यता के संबंध में करारबद्ध होना आवश्यक है।"

(सी) मौजूदा उप-विनियम 5 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है, अर्थात :

"सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, भारतीय कंपनियों की स्थापना / निवासी नागरिकों से अनिवासी एंटीटीयों को स्वामित्व अंतरण अथवा भारतीय कंपनी के नियंत्रण के संबंध में दिशानिर्देश

सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों / गतिविधियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन के अधीन होंगे जहां :

- (i) कोई भारतीय कंपनी जो विदेशी निवेश के साथ स्थापित हुई है और जिस पर निवासी एंटीटी का स्वामित्व नहीं है, अथवा
- (ii) कोई भारतीय कंपनी जो विदेशी निवेश के साथ स्थापित हुई है और जो निवासी एंटीटी द्वारा नियंत्रित नहीं है, अथवा
- (iii) कोई भारतीय कंपनी, जो फिलहाल निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में है/उनके द्वारा नियंत्रित है और ऐसी कंपनियों के स्वामित्व व नियंत्रण में है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है, के समामेलन, विलयन/विलगाव, अधिग्रहण, आदि के कारण अनिवासी एंटीटीयों को शेयरों के अंतरण/नए शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप कंपनी का नियंत्रण अनिवासियों को अंतरित हुआ/होता है, अथवा
- (iv) कोई भारतीय कंपनी, जो फिलहाल निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में है / उनके द्वारा नियंत्रित है और ऐसी कंपनियों के स्वामित्व व नियंत्रण में है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है, के समामेलन, विलयन/विलगाव, अधिग्रहण, आदि के कारण अनिवासी एंटीटीयों को शेयरों के अंतरण/नए शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप कंपनी का स्वामित्व अनिवासियों को अंतरित हुआ/होता है, अथवा
- (v) यह प्रमाणित किया जाता है कि विदेशी निवेशों में सभी विदेशी निवेश शामिल हैं जसे : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, QFI, अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश, एडीआर, जीडीआर, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB) और पूर्णतः, अनिवार्यतः, और अधिवेशात्मक परिवर्तनीय प्रेफ़रेंस शेयर / डिबेंचर तथा इस प्रकार के सभी निवेश, भले ही वे विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली की धारा 1, 2, 2ए, 3, 6, 8, 9, एवं 10 के अंतर्गत किए गए हों अथवा न हो।
- (vi) अनिवासी भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की धारा 4 के अंतर्गत किए गए निवेशों को निवासियों द्वारा किए गए घरेलू निवेश के समान माना जाएगा।
- (vii) कोई कंपनी, ट्रस्ट, एवं भागीदारी फर्म जो भारत से बाहर निगमित है और जिसका स्वामित्व और नियंत्रण अनिवासी भारतीयों के पास है, वह विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की धारा 4 के अंतर्गत निवेश करने के लिए पात्र होगी और ऐसे निवेश को भी निवासियों द्वारा किए गए घरेलू निवेश के समान माना जाएगा।"

(डी) उप-विनियम 6 में, मौजूदा खंड (ii) को संशोधित किया गया है, अर्थातः

"(ii) भारतीय कंपनियों / सीमित देयता भागीदारियों (LLPs) द्वारा किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :

ए. ऐसी कंपनियों / सीमित देयता भागीदारियों (LLPs) को अपने नए एवं वर्तमान वेंचरों (विस्तार कार्यक्रम के साथ अथवा उसके अलावा) सहित अपने डाउनस्ट्रीम निवेशों की सूचना विदेशी निवेश संबंधन बोर्ड की वैवसाइट <https://fipbindia.com> पर उपलब्ध फॉर्म में निवेश के 30 दिनों के भीतर SIA, DIPP और FIPB को देनी होगी, भले ही इसमें पूंजीगत लिखत आवंटित न की गई हो;

बी. वर्तमान भारतीय कंपनी में विदेशी इक्विटी के प्रतिफल के माध्यम से डाउनस्ट्रीम निवेश कंपनी के निदेशक बोर्ड के संकल्प द्वारा समर्थित हों और शेयरधारक-करार, यदि कोई हो, भी होना चाहिए;

सी. शेयरों का निर्गम / अंतरण / कीमत-निर्धारण / मूल्यांकण आदि सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत हो;

डी. डाउनस्ट्रीम निवेश के उद्देश्य से, भारीय कंपनियों / सीमित देयता भागीदारियों (LLPs), जो डाउनस्ट्रीम निवेश कर रही है, को विदेश से आवश्यक निधियाँ लाना अपेक्षित है, न कि घरेलू बाज़ार से लीवरेज के माध्यम से निधियाँ जुटानी हैं। हालांकि, इसके कारण घरेलू बाज़ार में कर्ज़ जुटाने से डाउनस्ट्रीम कंपनियों / सीमित देयता भागीदारियों (LLPs) को अपने प्रचलनों में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आंतरिक उपचय के माध्यम से डाउनस्ट्रीम निवेशों की अनुमति है (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उद्देश्य से, आंतरिक उपचय का अर्थ लागू करों के भुगतान के पश्चात प्राप्त लाभ का रिज़र्व फंड में अंतरण करने से है), बशर्ते वह उपर्युक्त खंड (i) के अधीन होगी और उसे नीचे विस्तार से वर्णित किया गया है:

ए. ऐसी भारतीय कंपनी में निवेश, जो केवल अन्य भारतीय कंपनी/यों की पूंजी में निवेश संबंधी गतिविधियों से जुड़ी है, को विदेशी निवेश की राशि अथवा सीमा पर ध्यान दिए बगैर सरकार / विदेशी निवेश संबंधन बोर्ड से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमोदित गतिविधियों को संचालित कर रही हैं, में विदेशी निवेश इस विनियमावली की अनुसूची-। के अनुलग्न बी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे।

बी. वे सभी कंपनियाँ, जो कोर इनवेस्टमेंट कंपनियाँ (CICs) हैं, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोर इनवेस्टमेंट कंपनियों (CICs) हेतु निर्धारित किए गए विनियामक ढांचे का भी अनुपालन करना होगा।

सी. स्वचालित मार्ग के तहत विनिर्दिष्ट गतिविधियों के संचालन के लिए एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों के लिए निर्धारित परफॉर्मेंस शर्तों को जोड़े बिना, ऐसी भारतीय कंपनियाँ जिनका कोई प्रचालन तथा कोई डाउनस्ट्रीम निवेश नहीं है, को स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेश प्राप्त करने हेतु की अनुमति है। हालांकि, ऐसी कंपनियों को सरकारी मार्ग के तहत अंतर्विद्यु गतिविधियों के संचालन हेतु विदेशी निवेश की राशि अथवा सीमा पर ध्यान दिए बगैर विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। आगे, जब भी ऐसी कंपनियां अपना कारोबार शुरू करेंगी तब उन्हें प्रवेश मार्ग पर संबन्धित सेक्टोरल कैप की निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं का अनुपालन करना होगा।

नोट : अन्य भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश, प्रवेश मार्ग पर निवेश से संबन्धित सेक्टोरल शर्तों एवं कैप की सीमाओं के अनुपालन के अधीन होगा।

ई) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर्ता भारतीय कंपनी प्रथमतः जिम्मेदार होगी कि वह अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से अपने डाउनस्ट्रीम निवेशों के मामले में एफडीआई संबंधी दिशानिर्देशों जैसे: प्रतिबंधित क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश न होने दें, प्रवेश मार्ग, सेक्टोरल कैप /शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। दूसरे स्तर पर सभी प्रकार के डाउनस्ट्रीम निवेशों के संबंध में अपने संविधिक लेखापरीक्षक से वार्षिक आधार पर फेमा प्रावधानों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करें। भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट वाले हिस्से में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए कि डाउनस्ट्रीम निवेशों के मामले में कंपनी ने मौजूदा फेमा प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में अपने संविधिक लेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। संविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी को फेमा प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में ड्रालिफ़ाइड रिपोर्ट दिये जाने पर कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को इस बारे में तत्काल सूचित करें, जिसके अधिकार-क्षेत्र में उस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, और इस सूचना के संबंध में वह रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से पावती प्राप्त कर लें। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय इस बारे में कार्यवाही रिपोर्ट फ़ाइल कर के इसे प्रधान मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह रोड, मुंबई – 400001 को भेजेंगे।”

सी. अनुसूची 1में,

(i) पैराग्राफ 2में, “बशर्ते यह भी कि शेयर और परिवर्तनीय डिवेंचर” शब्दों से शुरू होकर “....विनियम 14 में दी गई सीमा तक अनुमत” शब्दों से खत्म होने वाले पैराग्राफ को हटाया गया है।

(ii) पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ 4 में, खंड (iv) के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थातः

"(v) स्वाप शेयरों द्वारा, वर्षतेर्वेसे निवेश स्वचालित मार्ग वाले क्षेत्रों में पंजीकृत किसी कंपनी में किए गए हों और ऐसे निवेशों से संबद्ध भले ही इनकी निवेश-राशि कुछ भी क्यों न हो, स्वाप एग्रीमेंट में शामिल शेयरों का मूल्यांकन सेवी के पास पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर अथवा भारत से बाहर के मामले में मेजबान देश की किसी नियामक संस्था के पास पंजीकृत किसी निवेश बैंकर द्वारा किया जाए।

नोट :ऐसे क्षेत्र से संबद्ध कोई कंपनी, जिसमें विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन पर ही अनुमत है, सरकारी अनुमोदन प्राप्त कर के अनिवासियों को स्वाप के माध्यम से शेयर जारी कर सकती है।"

(iii) पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (सी) को हटाया गया है

(iv) 'अनुबंध-बी' मौजूदा टेबल को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टरों) में विदेशी निवेश की उच्चतम सीमाएं (Caps) एवं प्रवेश (entry) मार्ग

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैप का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
कृषि			
1	कृषि और पशुपालन		
	ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागवानी, मधुमक्खी-पालन तथा सब्जियों और मशरूम की खेती; बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन; सी) नियंत्रित परिस्थितियों में पशुपालन (श्वान प्रजनन सहित), मछली-पालन, जलीय कृषि (स्वाकल्चर); और डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं। टिप्पणी: उपर्युक्त के बलाबा, अन्य किसी कृषि क्षेत्र / गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।	100%	स्वचालित
1.1	अन्य शर्तें: 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती है: (i) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु-आर्द्रता और खेती की विधियों (culture) को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस से या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं – जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है। (ii) पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली इन्हें कवर करती है: (ए) स्टाल-फीडिंग के साथ गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत पशु-पालन। गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत जलवायु प्रणालियां (हवा-रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, झुंड पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां अपेक्षित होंगी जैसाकि राष्ट्रीय पशु नीति 2013 में विनिर्दिष्ट है तथा उन्हें मौजूदा "मानक परिचालन प्रणालियों एवं न्यूनतम मानक अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। (बी) मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर, हवा-रोशनी (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है। (iii) मत्स्यपालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है: (ए) मछलीघर (अक्वारियम) (बी) हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है और मछली के छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम जलवायु नियंत्रण के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण में उन्हें सेया जाता है।		

	(iv) मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है: (ए) कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान निर्धारित स्थानों पर, जंगल/वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमानों के साथ और जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम फीडिंग द्वारा मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन।		
2.	वृक्षारोपण		
2.1	i. चाय बागान क्षेत्र के तहत चाय की खेती शामिल है ii. कॉफी का वृक्षारोपण iii. रबड़ का वृक्षारोपण iv. इलाइची का वृक्षारोपण v. पाम-तेल के पेड़ों का वृक्षारोपण vi. ऑलिव औइल के पेड़ों का वृक्षारोपण नोट : वृक्षारोपण के मामलों में उपर उल्लिखित क्षेत्रों / गतिविधियों के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र में एकडीआई की अनुमति नहीं है।	100%	स्वचालित मार्ग
2.2	अन्य शर्तें भविष्य में भूमि-उपयोग में किसी भी प्रकार के बदलाव के मामले में संबंधित राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।		
3.	खनन		
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत धातुओं और गैर-धातुक अयस्कों का, जिनमें हीरा, स्वर्ण, चांदी, और मूल्यवान अयस्क शामिल हैं, खनन और अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज और इसके अयस्कों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।	100%	स्वचालित
3.2	कोयला और लिग्नाइट		
	(1) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के अधीन ऊर्जा परियोजनाओं, लोहा, इस्पात और सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा आबद्ध उपयोग के लिए कोयले और लिग्नाइट का खनन।	100%	स्वचालित
	(2) वॉशरीज़ जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना बशर्ते कंपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और धुले हुए कोयले या अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्र से प्राप्त साइज्ड कोयले की खुले बाजार में बिक्री नहीं करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड कोयले की आपूर्ति उन पक्षों को करेगी जो वॉशिंग या साइजिंग के लिए कोयला प्रसंस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं।	100%	स्वचालित
3.3	टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां		
3.3.1	क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तों के अधीन टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां	100%	सरकारी
3.3.2	अन्य शर्तें		

	<p>(i) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक करने के लिए एफडीआई निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी, नामतः</p> <p>(ए) प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत के भीतर स्थापित की जाएंगी;</p> <p>(बी) खनिज पृथक्करण के दौरान अपशिष्टों का निपटान परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों जैसे : परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 के अनुसरण में किया जाएगा।</p> <p>(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी की गई अधिसूचना सं. का.आ. 61(अ) में सूचीबद्ध 'निर्धारित पदार्थों' के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>		
	<p>स्पष्टीकरण:</p> <p>i. इलमेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन जैसे टाइटेनियम वाले अयस्कों के लिए टाइटेनियम डाईऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज के निर्माण से मूल्यवर्धन होता है। इलमेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाइल या टाइटेनियम स्लैग' जैसा मध्यवर्ती मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है।</p> <p>ii. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना में किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश में इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तो उपर्युक्त (i) (ए) में निर्धारित शर्तों को पूरा हुआ माना जाएगा।</p>		
4.	तेल और प्राकृतिक गैस		
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी पुनःगैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार अध्ययन और फार्मलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और विनियामक फ्रेमवर्क और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता के संबंध में सरकार की नीति के अधीन होगी।	100%	स्वचालित
4.2	मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में किसी प्रकार के विनिवेश या उनकी देशी इक्विटी को कम किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन।	49%	स्वचालित
5.	विनिर्मान (मैनुफैक्चरिंग)	100%	स्वचालित
	एफडीआई नीति के प्रावधानों की शर्तों के अधीन रहते हुए 'विनिर्मान (मैनुफैक्चरिंग)' क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेश की अनुमति है। यह भी कि, विनिर्माता सरकारी अनुमोदन के बिना भी अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स सहित थोक / रीटेल सेल के माध्यम से बेच सकता है।		
6.	रक्षा		
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है।	49%	49% तक सरकारी मार्ग से। 49% से अधिक सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमिटी द्वारा, मामले-दर-मामले के आधार पर, जहां इससे देश में आधुनिक और आत्यानिक तकनीक तक पहुँच हो संभव हो सकती है।

6.2	अन्य शर्तें			
	<p>i. अनुमत स्वचालित मार्ग के स्तर पर ऐसी कंपनी में नया विदेशी निवेश प्राप्त करना, जो औद्योगिक लाइसेन्स नहीं चाहती है, किन्तु उसके स्वामित्व का प्रकार बदलने अथवा मौजूदा निवेशक की कंपनी में हिस्सेदारी नए विदेशी निवेशक को अंतरित करने के परिणाम स्वरूप फ्रेश निवेश के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा।</p> <p>ii. लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से परामर्श के बाद औद्योगिक नीति एवं संबद्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे।</p> <p>iii. इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति रक्षा मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंधी क्लियरेंस तथा उनके दिशानिर्देशों के अधीन होगी।</p> <p>iv. निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उत्पाद डिजाइन एवं विकास के मामले में आत्मनिर्भर हो। उत्पादन सुविधा सहित निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त उद्यम कंपनी के पास भारत में निर्मित उत्पादों के मेट्रिसेस एवं लाइफ साइकिल सपोर्ट की भी सुविधा होनी चाहिए।</p>			
सेवा क्षेत्र				
सूचना सेवाएँ				
7	प्रसारण			
7.1	प्रसारण वाहक सेवाएं			
7.1.1	(1) टेलीपोर्ट (अप-लिंकिंग एचयूबी/टेलीपोर्ट की स्थापना) (2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) (3) केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करने वाले और डिजिटलाइजेशन एवं अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडशन का काम करनेवाले मल्टीज सिस्ट म ऑपरेटर (एमएसओ) (4) मोबाइल टीवी (5) हेड एंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस)	100%	49% तक स्वचालित मार्ग 49% से अधिक के लिए सरकारी मार्ग	
7.1.2	केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन और अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ))	100%	49% तक स्वचालित मार्ग। 49% से अधिक के लिए सरकारी मार्ग	
7.2	प्रसारण विषयक सेवाएं			
7.2.1	क्षेत्रीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो), एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम व शर्तों के अधीन होगी जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।	49%	सरकारी मार्ग	
7.2.2	“समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले” टी बी चैनलों की अपलिंकिंग	49%	सरकारी मार्ग	
7.2.3	“गैर समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले” टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग / टीवी चैनलों की डाउन-लिंकिंग	100%	स्वचालित मार्ग	
7.3	टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग/डाउन-लिंकिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सुसंगत अप-लिंकिंग/डाउन-लिंकिंग नीति के अनुपालन के अधीन होगी।			
7.4	उपर्युक्त वर्णित सभी सेवाओं में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) ऐसे सुसंगत विनियमों और नियमों व शर्तों के अधीन होंगे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हों।			
7.5	उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (FII) की सीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII), विदेशी पोर्टफालियो निवेशकों (FPIs), अनिवासी भारतीयों (NRIs), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB), [इन विनियमों की अनुसूची 10 के अंतर्गत जारी ईक्विटी शेयरों सहित निक्षेपागार रसीदें अथवा अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर अथवा अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट अथवा अन्य कोई प्रतिभूति जिसमें मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के अनुसार अंतर्लियित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है] ग्लोबल निक्षेपागार रसीदें (GDRs) और विदेशी एंटिटीज द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयर शामिल होंगे।]			

7.6	<p>उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों/नियमों के अधीन होगा:</p> <p>कंपनी के प्रमुख कार्यपालकों के लिए अधिदेशात्मक अपेक्षा</p> <p>(i) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।</p> <p>(ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), तकनीकी नेटवर्क परिचालन के प्रभारी मुख्य अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय नागरिक होने चाहिए।</p> <p>कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन</p> <p>(iii) कंपनी, निदेशक बोर्ड के सभी निदेशकों और ऐसे किसी प्रमुख कार्यपालकों जैसे प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी(सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (CSO) मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), कंपनी में वैयक्तिक रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदत्त पूँजी रखने वाले शेररधारकों या जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी से अपेक्षित होगा कि वे सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करें।</p> <p>कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी(COO) आदि जैसे प्रमुख कार्यपालकों की नियुक्ति के मामले में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।</p> <p>कंपनी के लिए यह वाध्यकर होगा कि वह निदेशक बोर्ड में कोई परिवर्तन करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करे।</p> <p>(iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों की उनके अभिनियोजन से पहले सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रयेक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा।</p> <p>अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन</p> <p>(v) यह अनुमति, अनुमति धारक /लाइसेंसी द्वारा अनुमति की वैधता-अवधि के दौरान सुरक्षा अनुमोदन बरकरार रखे जाने के अधीन होगी। सुरक्षा अनुमोदन वापस लिए जाने की स्थिति में दी गई अनुमति तत्काल खत्म की जा सकती है।</p> <p>(vi) अनुमति धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमति धारक/लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमति/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमति/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।</p> <p>इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क/सॉफ्टवेअर संबंधी अपेक्षा</p> <p>(vii) लाइसेंसी कंपनी के अधिकारी/पदाधिकारी, जो सेवाओं के विविसम्मत अवरोधन से संबंधित हैं, भारतीय नागरिक होंगे।</p> <p>(viii) इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क डायग्राम (नेटवर्क के तकनीकी व्यौरे) से संबंधित विवरण, केवल आवश्यक होने पर, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसी कंपनी की संबद्ध संस्था को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना किसी अन्य को दी जानी हो तो इसके लिए लाइसेंस-प्रदाता का अनुमोदन अपेक्षित होगा।</p> <p>(ix) जब तक सुसंगत कानून द्वारा अनुमत न हो, कंपनी ग्राहक का डेटाबेस भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी।</p> <p>(x) कंपनी अपने ग्राहकों की ऐसी पहचान अवश्य उपलब्ध कराएगी जिसका पता लगाया जा सके।</p> <p>सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण</p> <p>(xi) कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उनके उपकरण में ऐसे आवश्यक प्रावधान (हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर) उपलब्ध हों जिससे सरकार द्वारा जब कभी अपेक्षित हो किसी केंद्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी की जा सके।</p> <p>(xii) कंपनी सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के तहत या उनके द्वारा प्रसारण सेवा की सतत निगरानी के लिए अपने खर्चे पर निर्दिष्ट स्थान(नों) पर आवश्यक उपकरण, सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।</p> <p>(xiii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण</p>
-----	--

	<p>करने का अधिकार होगा। सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए किसी पूर्व अनुमति/सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों से अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी गतिविधियों और परिचालनों के किसी विशेष पहलू की सतत निगरानी के लिए सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। तथापि, सतत निगरानी केवल सुरक्षा से जुड़े पहलुओं तक सीमित होगी जिसमें आपत्तिजनक विषय की स्क्रीनिंग शामिल है।</p> <p>(xiv) ये निरीक्षण सामान्यतया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे।</p> <p>(xv) सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी सेवाओं से संबंधित ऐसी कोई सूचना समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए फार्मेट में प्रस्तुत करेगी।</p> <p>(xvi) अनुमतिधारक /लाइसेंसधारी भारत सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ट्राई (TRAI) या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को रिपोर्ट, खाते, प्राक्कलन, विवरणियां या ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी अपेक्षित आवधिक अंतरालों पर या अपेक्षित समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सेवा प्रदाताओं को सरकार के नामित पदाधिकारियों/ट्राई (TRAI) के पदाधिकारियों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) को अपनी प्रणालियों के परिचालन/विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित करना होगा।</p> <p>राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें</p> <p>(xvii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक /लाइसेंसधारी की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनहूं घोषित कर दिया जाएगा।</p> <p>(xviii) कंपनी किसी ऐसे उपकरण का आयात/उपयोग नहीं करेगी, जो गैर कानूनी और /या नेटवर्क सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो।</p> <p>अन्य शर्तें</p> <p>(xix) लाइसेंसकर्ता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित में या प्रसारण सेवाओं के उचित प्रावधान के लिए इन शर्तों में आशोधन करने या आवश्यक समझी जाने वाली नई शर्तों को शामिल करने का अधिकार होगा।</p> <p>(xx) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा स्थापित किए गए प्रसारण सेवा संबंधी उपकरण सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नियम, या विनियमन और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता हो।</p>		
8.	प्रिंट मीडिया		
8.1.	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26%	सरकार
8.2.	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26%	सरकार
8.2.1	अन्य शर्तें		
	(i) इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य से, 'पत्रिका' को जनता से संबंधित समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियों को गैर-दैनिक आधार पर प्रकाशित करने वाले नियतकालिक प्रकाशनों के रूप में परिभाषित किया गया है।		
	(ii) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशा-निर्देशों के भी अधीन होगा।		
8.3	वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका/विशेषज्ञता वाले जर्नल/ नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू वैधानिक ढांचे और इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा	100%	सरकार
8.4	विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकार

8.4.1	अन्य शर्तें		
	<p>(i) एफडीआई मूल विदेशी समाचार-पत्र के मालिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसका प्रतिकृति संस्करण भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>(ii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में निर्गमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा सकता है।</p> <p>(iii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण को प्रकाशित करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.03.2006 को जारी और समय समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।</p>		
9.	नागरिक उड्डयन		
9.1	<p>नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं/समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, रख-रखाव और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं।</p> <p>नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए :</p> <p>(i) 'हवाई अड्डा' से तात्पर्य है विमान के उतरने और उड़ान भरने का क्षेत्र जहां सामान्य तौर पर रनवे और विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधाएं होती हैं और एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 की धारा 2के खंड (2) में परिभाषित एरोड्रोम भी शामिल है।</p> <p>(ii) "एरोड्रोम" का तात्पर्य विमान के उतरने और उड़ान भरने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही तयशुदा या सीमित जमीन या पानी क्षेत्र से है, जिसमें सभी भवन, शेड, जहाज, गोदी और अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं।</p> <p>(iii) "हवाई अड्डा परिवहन सेवा" का तात्पर्य पारिश्रमिक के बदले व्यक्तियों, डाक या अन्य ऐसी चेतन या अचेतन के परिवहन की सेवा है जो वह एकल उड़ान या श्रृंखला उड़ान की सेवाओं के माध्यम से वी जा रही हो।</p> <p>(iv) "हवाई परिवहन उपकरण" का तात्पर्य उस उपकरण से है जिसके कारोबार में किराया या प्रतिफल के एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है।</p> <p>(v) "विमान के घटक" का तात्पर्य कोई हिस्सा या उपकरण का कोई भाग है जिसे जब विमान में लगाया जाता है तो उसकी सुदृढता और सही कार्य करने की क्षमता विमान की सुरक्षा या उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है।</p> <p>(vi) "हेलिकॉप्टर" का तात्पर्य वस्तु : ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या एक से अधिक शक्तिचालित रोटर की मदद से उड़ान भरने वाला वायु से भारी विमान से है।</p> <p>(vii) "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई परिवहन सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यतापूर्वक व्यवस्थित श्रृंखला में नियमित रूप से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो।</p> <p>(viii) "गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा न हो और इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है।</p> <p>(ix) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;</p> <p>(x) "समुद्री विमान" का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पानी से उड़ने और पानी पर उतरने के लिए सामान्य तौर पर सक्षम हो;</p> <p>(xi) "ग्राउंड हैंडलिंग" का तात्पर्य है (i) रैप हैंडलिंग, (ii) ट्राफिक हैंडलिंग, दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से विनिर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, और (iii) केंद्र सरकार द्वारा या तो रैप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि।</p>		
9.2	एयरपोर्ट		

	(ए) ग्रीनफील्ड परियोजनाएं (बी) मौजूदा परियोजनाएं	100% 100%	स्वचालित मार्ग 74% तक स्वचालित मार्ग से। 74% से अधिक के मामले में सरकारी मार्ग से
9.3	हवाई परिवहन सेवाएं		
	(1)(ए) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री सेवा (बी) क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवाएं	49% (NRI के लिए 100%)	स्वचालित
	(2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	100%	स्वचालित
	(3) हेलीकॉप्टर सेवा/समुद्री विमान सेवाएं जिनके लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) का अनुमोदन आवश्यक है	100%	स्वचालित
9.3.1	अन्य शर्तें		
	<p>ए) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन; गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं।</p> <p>बी) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युक्त में दी गई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइन, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान को परिचालित करने वाली कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति है।</p> <p>सी) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूँजी में उनकी चुकता पूँजी के 49% की सीमा तक निवेश करने की भी अनुमति है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :</p> <p>(i) यह सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।</p> <p>(ii) 49% की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश / एफपीआई निवेश शामिल होंगे।</p> <p>(iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूँजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनियमों/शेर्यरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।</p> <p>(iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं:</p> <p>ए) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है;</p> <p>बी) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और</p> <p>सी) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो।</p> <p>(v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़ने वाले सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती से पहले सुरक्षा संबंधी किलयरेंस लेना होगा।</p> <p>(vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित होने वाले सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा।</p> <p>टिप्पणी: (i) उपर्युक्त पैरा 9.3.1 और 9.3.2 में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा/प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो।</p> <p>(ii) 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के संबंध में अनिवासी भारतीयों को प्राप्त छूट उपर्युक्त मद 9.3.1(सी) (ii) में विनिर्दिष्ट निवेश क्षेत्र / दायरे पर भी लागू बनी रहेगी।</p> <p>(iii) उपर्युक्त मद 9.3.1(सी) में उल्लिखित नीति मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर लागू नहीं है।</p>	49% (एनआरआई के लिए 100%)	सरकारी
9.3.2	अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के परिचालन करने वाली भारतीय कंपनियों की पूँजी में विदेशी एयरलाइनों द्वारा निवेश		

9.4	नागरिक उद्ययन क्षेत्र के तहत अन्य सेवाएं		
	(1) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और सुरक्षा अनुमोदन के अधीन	100%	स्वचालित
	(2) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100%	स्वचालित
10.	पैकेज, पार्सल और अन्य मदों को ले जाने वाली कूरियर सेवाएं जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के दायरे में नहीं आती हैं, पत्रों के वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर	100%	स्वचालित
11.	निर्माण विकास : टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी संरचना		
11.1	निर्माण विकास परियोजनाएं (जिनमें टाउनशिप का विकास, आवास / वाणिज्यिक परिसर, सड़क अथवा पुलों, होटलों, रिसॉटर्स, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, मनोरंजन की सुविधाओं का निर्माण, शहर और क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं)	100%	स्वचालित
11.2	<p>निर्माण परियोजनाओं के प्रत्येक केज़ को एफडीआई नीति के अनुसार नयी परियोजना माना जाएगा। जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:</p> <p>(ए) (i) निवेशक को परियोजना पूरी होने अथवा बुनियादी (trunk) इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज एवं सीवेज के विकास के बाद परियोजना से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक परियोजना के तहत न्यूनतम विकसित किया जाने वाला क्षेत्र निम्नवत होगा:</p> <p>(ii) उपर्युक्त (ए) (i) में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, स्वचालित मार्ग के तहत परियोजना के पूरा होने से पूर्व निवेशक अपने विदेशी निवेश को एकिज्ञ अथवा प्रत्यावर्तित कर सकता है, वर्ते निवेश के प्रत्येक अंश पर गणना की गई लॉक-इन अवधि पूरी हो गई हो। इसके अलावा निवेश की राशि को प्रत्यावर्तित किए बिना एक अनिवासी से दूसरे अनिवासी को उसके हिस्सेदारी (stake) के अंतरण के लिए न तोलांक-इन अवधि की शर्तें लागू होंगी और न ही सरकारी अनुमोदन की।</p> <p>(बी) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और राज्य सरकार/नगरपालिका/संबंधित स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि के उपयोग संबंधी अपेक्षाओं एवं सामुदायिक सुविधाओं और आम सुविधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।</p> <p>(सी) भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को केवल विकसित भूखंड बेचने की अनुमति होगी। इस नीति के प्रयोजनार्थ "विकसित भूखंड" का अभिप्राय ऐसे भूखंड से है जहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जैसे सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज एवं सीवेज की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हों।</p> <p>(डी) भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगी जिनमें इमारत/ले-आउट योजना(प्लान), आंतरिक और आस-पास के क्षेत्रों (peripheral areas) और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास, विकास, बाह्य विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान, संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के लागू नियमों/उप विधियों/ विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन शामिल होगा।</p> <p>(अ) इमारत/डेवलपमेंट प्लान को अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने वाली संबंधित राज्य सरकार/ नगरपालिका/स्थानीय निकाय डेवलपर द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किए जाने की निगरानी करेगी।</p> <p>नोट : (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी ऐसी कंपनी (एंटीटी) में अनुमत नहीं है जो रियल इस्टेट कारोबार, फार्म हाउसों के कंस्ट्रक्शन एवं अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकार (TDRs) में संलग्न हो अथवा उसमें संलग्न होने का प्रस्ताव करती हो।</p> <p>'रियल इस्टेट कारोबार' का अभिप्राय वही है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के साथ पठित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी में दिया गया है अर्थात् भूमि और अचल संपत्ति का सौदा लाभ कमाने अथवा आय के अर्जन के दृष्टिकोण से किया जाता हो एवं इसमें टाउनशिप का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इनका, टाउनशिप निर्माण शामिल नहीं हैं।</p> <p>(ii) उपर्युक्त मद (ए) की शर्तें होटल और टूरिस्ट रिज़ॉर्ट; अस्पतालों; विशेष आर्थिक क्षेत्रों; शैक्षिक संस्थाओं; वृद्धाश्रमों और अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में लागू नहीं होंगी।</p>		

	<p>(iii) परियोजना की पूर्णता स्थानीय उप-विनियमों / नियमों और राज्य सरकार के अन्य विनियमों के अनुसार परिभाषित होगी।</p> <p>(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि टाउनशिप, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और विज़नस सेंटर की पूर्ण परियोजनाओं के परिचालन और प्रबंधन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप, निवेशक कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण का अंतरण की भी अनुमति है। तथापि, एफडीआई के प्रत्येक अंश के संदर्भ में तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि होगी और इस अवधि के दौरान अचल संपत्ति के अंतरण की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>(v) FOI नीति के संबंध में "अंतरण" में निम्नलिखित शामिल हैं, -</p> <ul style="list-style-type: none"> ए. संपत्ति की विक्री, विनिमय अथवा त्याग ; अथवा बी. उसमें अधिकारों (rights) का विलोपन, अथवा सी. किसी कानून के तहत संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण; अथवा डी. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53ए के संदर्भ में कांट्रैक्ट के पेरफोर्मेंस के भाग के रूप में किया गया ऐसा कोई लेनदेन जिसमें अचल संपत्ति ली अथवा धारण की गई हो; ई. ऐसा कोई लेनदेन, जो किसी कंपनी में शेयरों के अर्जन अथवा किसी करार अथवा अन्य किसी व्यवस्था के तहत, जैसी भी हो, के परिणामस्वरूप यदि किसी अचल संपत्ति का लाभ लेने अथवा अंतरण प्राप्त होता हो। 		
12.	औद्योगिक पार्क – नए और मौजूदा	100%	स्वचालित
12.1	<p>(i) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें विकसित की गई भूमि के प्लॉटों या इमारतदार क्षेत्र या संयुक्त रूप से साझा सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों के तौर पर उच्च कोटि की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है और इन्हें सभी आवंटित इकाइयों को औद्योगिक कार्यकलाप के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है।</p> <p>(ii) "बुनियादी संरचना" का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं और इनके अंतर्गत सड़कों (पहुंचने के मार्ग सहित), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सहित रेलवे लाइनें/साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें, जल-आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकूलन आदि शामिल हैं।</p> <p>(iii) "साझा सुविधाओं" से अभिप्रेत है औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं जिनमें बिजली, सड़कों (पहुंचने के मार्ग सहित), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सहित रेलवे लाइनें/साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें, जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य (common) टेस्टिंग, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैटीन, कन्वेन्शन/सम्मेलन भवन, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं।</p> <p>(iv) औद्योगिक पार्क में "आवंटनीय क्षेत्र" का तात्पर्य है :</p> <p>(ए) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में – इकाइयों को आवंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट क्षेत्र, जिसमें साझा सुविधाओं वाला क्षेत्र शामिल नहीं है।</p> <p>(बी) इमारतदार क्षेत्र के मामले में – फर्शी क्षेत्र और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र।</p> <p>(सी) डेवलप की गई भूमि और इमारतदार क्षेत्र के संयुक्त रूप के मामले में – इकाइयों को आवंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट और फर्शी क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा के लिए प्रयुक्त साइट क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं है।</p> <p>(व) "औद्योगिक कार्यकलाप" से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस और जल आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपूर्ति; डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस संबंधी गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक विषय-वस्तु का संवितरण; कंप्यूटर से संबंधित अन्य गतिविधियां; जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज विज्ञान/जीव-विज्ञान, नैसर्जिक</p>		

	विज्ञान और इंजीनियरी पर आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान व विकास; व्यवसाय एवं प्रबंधन संबंधी परामर्शी गतिविधियां; तथा वास्तु कला, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी गतिविधियां।		
12.2	<p>औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले एफडीआई को उपर्युक्त पैरा 11 में बताई गई निर्माण विकास परियोजनाओं आदि के लिए प्रयोज्य शर्तों का पालन करने के लिए वाध्य नहीं किया जाएगा, बर्ते कि औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :</p> <p>(i) उनमें कम-से-कम 10इकाइयां शामिल हों और कोई भी एकल इकाई आवंटनीय क्षेत्र का 50 % से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेगी;</p> <p>(ii) औद्योगिक गतिविधि के लिए आवंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आवंटनीय क्षेत्र के 66% से कम न हो।</p>		
13.	उपग्रह – स्थापना और परिचालन		
13.1	उपग्रह-स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष विभाग/ इस्तो के क्षेत्र-विशेष संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन है।	100%	सरकार
14.	निजी सुरक्षा एजेंसियां	49%	सरकार
15.	<p>दूरसंचार सेवाएं (दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी- सहित)</p> <p>दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी- सहित सभी दूर संचार सेवाएं अर्थात्- मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रॅकड सर्विसेज (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वाइस मेल/आडियोटेक्स/ यूएमएस, आईपीएलसी की पुनः बिक्री, मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी- (डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस, टावर प्रदाता) प्रदाता, केवल अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़िकर</p>	100%	<p>49% तक स्वचालित मार्ग</p> <p>49% से अधिक सरकारी मार्ग</p>
15.1.1	अन्य शर्तें :		
	100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें से 49% स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एवं 49% से अधिक सरकारी मार्ग के तहत होगा, बर्ते दूर संचार विभाग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित लाइसेंसी के साथ-साथ निवेशक द्वारा लाइसेंसिंग एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन किया जाए, केवल "अन्य सेवाएं प्रदाताओं" को छोड़िकर जिन्हें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।		
16.	व्यापार (ट्रेड)		
16.1	(i) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार (एमएसई से सोर्सिंग सहित)	100%	स्वचालित मार्ग
16.1.1	परिभाषा:		
	कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार का अभिप्राय है कि खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या अन्य व्यावसायिक कारोबारी प्रयोक्ताओं या अन्य थोक व्यापारियों तथा सम्बद्ध सहायक सेवाप्रदाताओं को वस्तुओं / व्यापारिक माल की बिक्री करना। तदनुसार, थोक व्यापार का अर्थ होगा – व्यापार, कारोबार तथा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के लिए बिक्री। बिक्री थोक है या नहीं उसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री किन प्रकार के ग्राहकों को की गई है, न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर। थोक व्यापार में पुनः बिक्री, प्रसंस्करण तथा उसके बाद बिक्री, एक्स-पोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात/एक्स-बॉन्डेड गोदाम कारोबारी बिक्री तथा बी-2-बी ई-कॉर्मर्स शामिल होंगी।		

16.1. 2	<p>कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार के संबंध में दिशा-निर्देश</p> <p>(ए) थोक व्यापार करने के लिए, राज्य सरकार/सरकारी निकाय/सरकारी प्राधिकरण/स्थानीय स्वशासन निकाय के संबंधित अधिनियमों/विनियमों/नियमों/आदेशों के अधीन अपेक्षित लाइसेंस/पंजीकरण/परमिट प्राप्त किए जाने चाहिए। (बी) सरकार को की गई विक्री के मामलों को छोड़कर, थोक व्यापारी द्वारा 'कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार' को वैध कारोबारी ग्राहकों के साथ विक्री तभी माना जाएगा जब थोक व्यापार निम्न लिखित के साथ किया जाएः</p> <p>(i) विक्री कर/वैट पंजीकरण/सेवा कर/उत्पाद शुल्क पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं; अथवा</p> <p>(ii) सरकारी प्राधिकारी/सरकारी निकाय/स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी द्वारा दुकान तथा स्थापना अधिनियम के अधीन जारी व्यापार लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र/पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं जिससे यह पता चले कि लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, रखने वाली संस्था/व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े कारोबार में लगे हों; अथवा</p> <p>(iii) सरकारी प्राधिकारियों/स्थानीय स्वशासन निकायों से खुदरा कारोबार करने के लिए परमिट/ लाइसेंस आदि)जैसे कि हॉकरी के लिए तहवजारी तथा उसी प्रकार के लाइसेंस (रखने वाली संस्थाएं; अथवा</p> <p>(iv) निगमन प्रमाणपत्र रखने वाली संस्थाएं या अपने स्वयं के उपभोग के लिए सोसाइटी या सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकरण वाली संस्थाएं।</p> <p>टिप्पणी :कोई संस्था, जिसके साथ थोक व्यापार किया गया है, को इन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी।</p> <p>(पी) विक्री का पूरा रिकार्ड जैसे कि संस्था का नाम, संस्था का स्वरूप, पंजीकरण / लाइसेंस/ परमिट आदि संछया, विक्री की राशि, आदि दैनिक आधार पर रखे जाने चाहिए।</p> <p>(डी) एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं का थोक व्यापार करने की अनुमति है। लेकिन, समूह के रूप में ली गई कंपनियों का आपसी थोक व्यापार उनके थोक मूल्य उद्यम के कुल टर्न-ओवर के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>(इ) लागू विनियमों के अधीन सामान्य कारोबारी प्रथा के रूप में थोक व्यापार किया जा सकता है, जिसमें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है।</p> <p>(एफ) थोक/कैश एंड कैरी व्यापारी पैरा 16.3 की शर्तों के अनुसरण में एकल ब्रांड रीटेल व्यापार कर सकता है। थोक/कैश एंड कैरी तथा रीटेल कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने कारोबार के दोनों अंगों के लिए अलग-अलग लेखा वहियाँ बनाएँ एवं सांविधिक ऑडिटर के द्वारा उनका विधिवत रूप से ऑडिट कराएँ। थोक/कैश एंड कैरी तथा रीटेल कारोबार नामक कारोबार के दोनों अंगों हेतु उपलब्ध एफडीआई शर्तों का संबंधित कारोबार-अंग के अनुसार अलग-अलग अनुपालन किया जाए।</p>		
16.2	बी टू बी ई-कॉर्मस गतिविधियां	100%	स्वचालित
	ई-कॉर्मस गतिविधियों का अभिप्राय है - ई-कॉर्मस प्लैटफॉर्म के माध्यम से किसी कंपनी द्वारा खरीदने और बेचने की गतिविधि करना। ऐसी कंपनियां केवल बी2बी ई-कॉर्मस करेंगी न कि खुदरा व्यापार। अन्य बातों के साथ-साथ, इसका यह अभिप्राय होगा कि देशी (घरेलू) व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान प्रतिबंध ई-कॉर्मस पर भी लागू होंगे।		
16.3	एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार	100%	49% तक स्वचालित मार्ग 49% से अधिक सरकारी मार्ग
	(1) एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथा विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बढ़ी सोर्सिंग को प्रोत्साहन देना, तथा वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना। 2) एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएँगा: (ए) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्रैंड'(सिंगल ब्रैंड) के होंगे। (बी) एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात् भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन बेचे जाने चाहिए।		

<p>(सी) 'एकल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है। किसी अनिवासी संस्था / संस्थाओं को, चाहे ब्रैंड का मालिक हो अथवा अन्यथा, विशिष्ट ब्रैंड के संबंध में सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार के लिए ब्रैंड के मालिक के साथ किए गए कानूनी तौर पर मान्य करार के अधीन, विशिष्ट ब्रैंड के लिए देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करने वाली संस्था इस आशय का प्रमाण अनुमोदन प्राप्त करते समय प्रस्तुत करेगी, जिसमें उपर्युक्त शर्त के अनुपालन को विशिष्ट रूप से दर्शनी वाले लाइसेंस / फैन्चाइज़ / उप लाइसेंस करार की प्रति शामिल होगी। स्वचालित मार्ग के लिए अपेक्षित साक्ष्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पास और अनुमोदन लेने वाले मामले SIA/FIPB के पास फाइल किए जाने चाहिए।</p> <p>(डी) 51% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य के 30% की सोर्सिंग भारत से की जाएगी, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग (MSME), ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरियता दी जाएगी। देशी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जांच कंपनी द्वारा रखे गए विधिवत प्रमाणित खातों से सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाएगी। खरीद की इस अपेक्षा को कंपनी द्वारा कारोबार शुरू करने के समय से अर्थात प्रथम स्टोर की शुरुआत से वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो।</p> <p>(अ) उपर्युक्त पैरा की शर्तों के अधीन, जिन सिंगल ब्रांड रीटेल कंपनियों के स्टोर भौतिक रूप से मौजूद हैं, उन्हें ई-कॉर्मस के माध्यम से रीटेल करने की अनुमति होगी।</p> <p>(3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार का प्रस्ताव करने वाली कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में औद्योगिक सहायता सचिवालय (SIA) को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उन उत्पादों / उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रांड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में, खाद्य उत्पादों को छोड़कर, उत्पादों / उत्पाद की श्रेणियों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध करायी जाएगी।</p> <p>(4) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए FIPB द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।</p> <p>नोट :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. भारतीय ब्रांड के सिंगल ब्रांड रीटेल व्यापार संबंध में उपर्युक्त पैरा (2)(बी) एवं (2)(डी) की शर्तें लागू नहीं होंगी। ii. भारतीय निर्माता को अपने निर्मित उत्पादों को ई-कॉर्मस सहित थोक, खुदरा अथवा किसी भी रूप में बेचने की अनुमति है। iii. भारतीय निर्माता यदि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी है, जो भारतीय ब्रांड की मालिक है और जो भारत में निर्माण करती है, को उत्पादों के मूल्य के अनुसार अपने कम से कम 70% उत्पादों का रीटेल घरेलू आधार पर और अधिकतम 30% उत्पादों का रीटेल भारतीय निर्माताओं के माध्यम से कर सकती है। iv. भारतीय ब्रांड का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए और/अथवा ऐसी कंपनियों के पास होना चाहिए जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो। v. "अत्याधुनिक एवं उच्चतम तकनीक" वाले उत्पादों से संबंधित एंटीटीयों और जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है ऐसे मामलों में सिंगल ब्रांड ट्रेड के विषय में सरकार सोर्सिंग नियमों को शिथिल कर सकती है। 	<p>51%</p>	<p>सरकार</p>
---	------------	--------------

<p>(i) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे पोलट्री, मत्स्यपालन तथा मांस उत्पाद सहित ताजे कृषि उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं।</p> <p>(ii) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की लायी जाने वाली न्यूनतम राशि 100मिलियन अमरीकी डालर होगी।</p> <p>(iii) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से, प्रथम किस्त के रूप में लाए गए 100मिलियन अमरीकी डालर की कम से कम 50% राशि 3वर्ष के भीतर 'बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेश की जाएगी, जहां बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधियों पर पूंजी व्यय शामिल होगा; उदाहरण के लिए, बैंक-एन्ड-इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि बाजार उत्पाद, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि में किए गए निवेश शामिल होंगे। भूमि की लागत तथा किराए पर किए गए व्यय, यदि कोई हों, की गणना बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन में शामिल नहीं होगी। बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में बाद में किए जाने निवेश कारोबारी अपेक्षाओं के आधार पर मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापारी द्वारा किए जाएंगे।</p> <p>(iv) खरीद गये विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के मूल्य का कम-से-कम 30% भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) से सोर्स किया जाएगा जिनका संयत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 2 00.मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो। यह मूल्यन संस्थापन के समय का मूल्य है, जिसमें मूल्यहास का प्रावधान (शामिल) नहीं है। 'लघु उद्योग' का दर्जा खुदरा व्यापारी के साथ पहली बार जुड़ने के समय का ही है और ऐसा उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योग' के रूप में पात्र माना जाता रहेगा, भले ही खुदरा व्यापारी के साथ जुड़ाव के दौरान उसके उक्त 2 00.मिलियन अमरीकी डालर के निवेश के आकार में इजाफा हो जाए। कृषि सहकारी समितियों और कृषक सहकारी समितियों से सोसिंग को भी इसी श्रेणी में माना जाएगा। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा।</p> <p>(v) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या (i), (ii) और (iv) की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विश्वित प्रमाणित खाते रखेंगे।</p> <p>(vi) खुदरा बिक्री केंद्र केवल उन्हीं नगरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 2011की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य नगरों भी स्थापित किए जा सकते हैं जिनमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल/शहरी स्थानों के 10किलोमीटर में आने वाले आस-पास के क्षेत्र भी शामिल होंगे; खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे।</p> <p>(vii) कृषि उत्पादों की खरीद करने का पहला अधिकार सरकार का होगा।</p> <p>(viii) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (इनेबिलिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्र उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएं जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की सहमति दी है, या भविष्य में सहमति देंगे। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनकी सूची नीचे क्रमांक (2) में दी गयी है। भविष्य में इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमति देने की सूचना औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दी जाएगी और तदनुसार, वह क्रमांक (2) में शामिल कर दी जाएगी। खुदरा बिक्री केंद्र की स्थापना दुकान तथा स्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों/विनियमों के अनुपालन में की जाएगी।</p> <p>(ix) ई-कॉर्मस के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार की अनुमति बहु-ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को नहीं होगी।</p> <p>(x) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एकआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।</p>
--

	(2) पैराग्राफ 16.4.(1) (viii) में उल्लिखित राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों की सूची <ol style="list-style-type: none"> आंध्र प्रदेश असम दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर कर्नाटक महाराष्ट्र मणिपुर राजस्थान उत्तराखण्ड दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (केंद्र शासित क्षेत्र) 		
16.5	शुल्क रहित (छूटी फ्री) दुकाने	100%	स्वचालित
	(i) शुल्क रहित (छूटी फ्री) दुकानों का अर्थ वे दुकानें हैं जो सीमाशुल्क क्षेत्र के तहत हैं और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों/अंतरराष्ट्रीय समुद्री बन्दरगाहों एवं लैंड कस्टम स्टेशनों के क्षेत्र में स्थापित दुकाने हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाज ही होती है। (ii) शुल्क रहित (छूटी फ्री) दुकानों में विदेशी निवेश कस्टम्स अधिनियम, 1962 तथा अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन होगा। (iii) शुल्क रहित (छूटी फ्री) दुकानों को देश के घरेलू टेरीफ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रीटेल गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।		
	वित्तीय सेवाएं नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी:		
एक.1	परिसंपत्तियों की (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)		
एक. 1.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरकारी एक्ट) की धारा 3के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो।	100%	49% तक स्वचालित मार्ग से 49% से अधिक सरकारी मार्ग से
एक.1.1.2	अन्य शर्तें		
	(i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनी की पूँजी में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक और सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 49% से अधिक निवेश कर सकते हैं। (ii) कोई भी प्रवर्तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा विदेशी संस्थागत निवेश/विदेशी पोर्टफालियो निवेश के मार्फत एकल प्रवर्तक के रूप में किसी भी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के 50% से अधिक शेयरों का धारण नहीं कर सकता है। (iii) किसी भी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफालियो निवेशक की कुल शेयरधारिता प्रदत्त पूँजी के 10% से कम होगी। (iv) विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफालियो निवेशक रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफालियो निवेशक एसआर योजना की प्रत्येक श्रृंखला में 74% तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश समय-समय पर कार्पोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेश/विदेशी पोर्टफालियो निवेश के लिए विनिर्दिष्ट सीमा में और मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियमावली के अंतर्गत सेक्टोरल कैप के अनुपालन में होनी चाहिए। (v) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरकारी एक्ट) की धारा 3(3)(एक) के प्रावधानों के अधीन होंगे।		

एक.2	बैंकिंग-निजी क्षेत्र		
एक. 2.1	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	74%	49% तक स्वचालित 49% से अधिक और 74% तक सरकारी मार्ग से
एक. 2.2	अन्य शर्तें		<p>1) इस 74% की सीमा में एकआईआई/एफपीआई, एनआरआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किए गए निवेश और पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, DRs सहित मौजूदा शेयरधारकों द्वारा अर्जित शेयर इसमें शामिल होंगे।</p> <p>2) किसी निजी बैंक में सभी स्रोतों से होने वाला समग्र विदेशी निवेश उस बैंक की प्रदत्त पूँजी के अधिकतम 74% तक ही अनुमत होगा। किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को छोड़कर अन्य निजी बैंकों में प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम 26% हिस्सा सदैव निवासियों (भारतीयों) के पास रहेगा।</p> <p>3) उल्लिखित शर्तें निजी क्षेत्र के मौजूदा बैंकों में किए जाने वाले सभी निवेशों पर भी लागू होंगी।</p> <p>4) FII / FPI और NRI द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जाने वाले निवेश की अनुमत सीमाएं निम्नानुसार होंगी:</p> <p>(i) FII / FPI के मामले में अब तक की भाँति किसी एक एकआईआई/ एफपीआई की धारिता कुल प्रदत्त पूँजी के 10% से कम रहेगी और सभी FII / FPI/ QFI के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूँजी के 24% से अधिक नहीं होगी। इस सीमा को संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूँजी के 74% तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक के निदेशक मंडल ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो और तदनंतर आम सभा द्वारा भी इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया गया हो।</p> <p>(ए) एनआरआई के मामले में, अब तक की भाँति, एकल धारिता प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूँजी के 5% तक सीमित है और समग्र सीमा प्रत्यावर्तन तथा गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूँजी के 10% से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि उक्त बैंकिंग कंपनी अपनी आम सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित करती है तो उसमें एनआरआई धारिता को प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूँजी के 24% तक रखने की अनुमति दी जा सकती है।</p> <p>(बी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम / सहायक रखने वाले निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किए जाएंगे ताकि वह बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के परामर्श से यह सुनिश्चित कर सके कि बीमा क्षेत्र में विदेशी शेयरधारिता ने 49% की सीमा को भंग नहीं किया है।</p> <p>(सी) FDI के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए विनियम 14(5) के अनुसार यथा लागू रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा बनी रहेगी।</p> <p>(डी) इन मामलों में रिज़र्व बैंक और सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं इरडा जैसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियां एवं कार्यविधियां लागू बनी रहेंगी।</p> <p>(अ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा के मार्फत अर्जन के परिणाम स्वरूप किसी बैंक की प्रदत्त पूँजी के 5% या उससे अधिक पर उसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण हासिल होता हो तो ऐसे मामले में निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा के मार्फत अर्जन से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश अनिवासी निवेशों पर भी लागू होंगे।</p> <p>(ii) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था/कंपनी की स्थापना</p> <p>(ए) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था, दोनों में से किसी एक को ही रखने की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(बी) ऐसे विदेशी बैंक जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा विनियमित हैं और रिज़र्व बैंक की लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें 100% प्रदत्त पूँजी को धारित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे भारत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित कर सकें।</p> <p>(सी) कोई विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अर्थात् (i) शाखाएँ (ii) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था और (iii) निजी बैंक में अधिकतम 74% समग्र विदेशी निवेश सहित एक सहायक संस्था के रूप, में से किसी एक चैनल के द्वारा ही परिचालन कर सकता है।</p>

	<p>(डी) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित कर अथवा नए बैंकिंग लाइसेंस के द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। किसी विदेशी बैंक को निजी क्षेत्र के किसी मौजूदा बैंक के शेरयों का अर्जन कर एक सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी बर्तने ऊपर पैरा (i)(बी) में दी गई शर्त के अनुरूप निजी क्षेत्र के संबंधित बैंक की कम से कम 26% प्रदत्त पूँजी हमेशा निवासियों की धारिता में रहे।</p> <p>(ई) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधी सभी अपेक्षाओं और निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए मोटे तौर पर लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।</p> <p>(एफ) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना से संबंधित दिशानिर्देश रिजर्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।</p> <p>(जी) किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में अपनी सहायक संस्था की स्थापना करने अथवा अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित सभी आवेदन रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> <p>(iii) इस समय बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार 10% तक सीमित है और इसे संभावित निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कोई भी परिवर्तन, अंतिम नीतिगत निर्णय लिए जाने और संसद का उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।</p>			
एफ.3	बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र			
एफ.3.1	बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र	20%	सरकारी मार्ग से	
	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 के अधीन है।			
	यह सीमा (20%) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों पर भी लागू है।			
एफ.4	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)			
एफ.4.1	1. पण्यों की फ्यूचर्स ट्रेडिंग को फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत विनियमित किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही कमोडिटी एक्सचेंज पण्यों के फ्यूचर्स बाजार की बुनियादी कंपनियां हैं। वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य सर्वोत्तम पद्धतियों, आधुनिक प्रबंधन कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया कि पण्य बाजारों में विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जाए।			
	2. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,			
	(i) "पण्य बाजार" फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो पण्यों के बायदा संविदा कारोबार के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है।			
	(ii) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जिसे फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल मान्यता प्रदान की गई है।			
	(iii) "संस्था (असोसिएशन)" से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे निकाय, निगमित अथवा अनिगमित, से हैं जो किसी वस्तु अथवा कमोडिटी डेरिवेटिव की विक्री या खरीद के कारोबार को विनियमित और नियंत्रित करने के प्रयोजन से गठित किया गया है।			
	(iv) "फॉरवर्ड संविदा" से अभिप्राय ऐसी संविदा से है जो वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए है और जो एक तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है।			
	(v) "कमोडिटी डेरिवेटिव" से अभिप्राय है –			
	• वस्तुओं की सुपुर्दगी की एक संविदा जो तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है; अथवा			
	• मूल्यों में अंतर की एक ऐसी संविदा जिसका मूल्यांकन कीमतों अथवा ऐसी अन्तर्निहित वस्तुओं या गतिविधियों, सेवाओं, अधिकारों, हितों और घटनाक्रमों के मूल्य सूचकांकों पर आधारित हो, जो केंद्र सरकार द्वारा सेवी के परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है लेकिन इसमें प्रतिभूतियां शामिल नहीं होंगी।			
एफ.4.2	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)	49%	स्वचालित मार्ग से	
एफ.4.3	अन्य शर्तें :	(i) FII/FPI द्वारा की जाने वाली खरीद द्वितीयक बाजार तक ही सीमित होगी।		

	(ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित, इन कंपनियों की इंक्विटी में 5% से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकते हैं। (iii) कमोडिटी एक्स्चेंज में किया जाने वाला विदेशी निवेश केंद्र सरकार/सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।		
एक.5	ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)		
एक.5.1	ऋण आसूचना कंपनियां	100%	स्वचालित मार्ग से
एक.5.2	अन्य शर्तें : (1) ऋण आसूचना कंपनियों में विदेशी निवेश प्रत्यय विषयक जानकारी (ऋण आसूचना) कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधीन होगा। (2) विदेशी निवेश की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी के अधीन होगी। (3) इस प्रकार के एफआईआई/एफपीआई निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता 10% से कम हो; (बी) किसी भी अधिग्रहण के, 1% से अधिक होने पर इसकी सूचना अनिवार्यतः भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाएगी; और (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले FII, अपनी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।		
एक. 6	प्रतिभूति बाजार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी		
एक.6.1	सेबी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाजारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाजार, निक्षेपागार और समाशोधन निगम	49%	स्वचालित मार्ग से
एक.6.2	अन्य शर्तें:		
एक.6.2.1	FII / FPI केवल द्वितीय बाजारों में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं		
एक.7.	बीमा		
एक.7.1	बीमा (i) बीमा कंपनी (ii) बीमा ब्रोकर (iii) थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (iv) सर्वेयर और हानि आकलक (loss assessors) (v) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों अंतर्गत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाएं	49%	26% तक स्वचालित मार्ग से 26% से अधिक और 49% तक सरकारी मार्ग से
एक.7.2	अन्य शर्तें: (ए) किसी भी भारतीय बीमा कंपनी के इंक्विटी शेयरों में पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा उसके इंक्विटी शेयरों में की जाने वाली विदेशी निवेश की समग्र होल्डिंग उस भारतीय बीमा कंपनी की प्रदत्त इंक्विटी पूँजी के 49% से अधिक नहीं होगी; (बी) भारतीय बीमा कंपनी में 26% से अधिक एवं 49% की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों में विदेशी निवेश सरकारी मार्ग के तहत होगा। (सी) इस क्षेत्र में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा और इस शर्त के अधीन होगा कि एफडीआई लाने वाली कंपनियां बीमा गतिविधियों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेंगी। (डी) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करे कि उसका स्वामित्व एवं नियंत्रण हमेशा निवासी भारतीय एंटिटीयों के हाथ में ही रहे जैसाकि वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा निर्धारित / अधिसूचित किया गया हो।		

	<p>(अ) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश केमा विनियमावली, 2000 के उप विनियम (2), (2ए), (3) एवं (8) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली के प्रावधानों के अधीन होगा।</p> <p>(एफ) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केमा के तहत जारी कीमत निधरिण संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।</p> <p>(जी) 49% तक की 'विदेशी ईंकिटी निवेश सीमा' संबंधी उल्लिखित शर्तें बीमा ब्रोकरों, थर्ड पार्टी एड्विनिस्ट्रटरों, सर्वेयर एवं हानि आकलकों एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के तहत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं पर भी लागू होंगी।</p> <p>(एच) बशर्ते यह कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यवर्ती बीमा संस्था/कंपनी के रूप में अनुमत कोई एंटिटी यदि बैंक है, जिसका प्राथमिक कारोबार बीमा क्षेत्र से भिन्न (अर्थात गैर-बीमा) है, तो उसमें विदेशी ईंकिटी निवेश की उच्चतम सीमा उस क्षेत्र के लिए लागू सीमा होगी और यह भी कि किसी भी वित्त वर्ष में उस एंटिटी का अपने प्राथमिक कारोबार (गैर-बीमा क्षेत्र से) से प्राप्त राजस्व उसके समग्र राजस्व के 50% से अधिक होना चाहिए।</p> <p>(आई) बैंक प्रवर्तित (promoted) बीमा कंपनियों के लिए "बैंकिंग-निजी क्षेत्र" संबंधी पैराग्राफ सं. एफ 2. 2(3)(i) (सी) एवं (डी) के उपबंध लागू होंगे।</p> <p>(जे) 'नियंत्रण', 'ईंकिटी शेयर पूँजी', 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)', 'विदेशी निवेशक', 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', 'भारतीय बीमा कंपनी पर भारतीय नियंत्रण', 'भारतीय स्वामित्व', 'अनिवासी एंटिटी', 'सार्वजनिक वित्तीय संस्था', 'निवासी भारतीय नागरिक', 'कुल विदेशी निवेश' शब्दावली का अर्थ वही होगा जो 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.115 (ई) में दिया गया है।</p>		
एफ.8.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)		
एफ.8.1	<p>गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में स्वचालित मार्ग के तहत केवल निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ही विदेशी निवेश की अनुमति होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) मर्चेन्ट बैंकिंग (ii) हामीदारी (iii) पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएं (iv) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं (v) वित्तीय परामर्श (vi) शेयर ब्रोकिंग (vii) आस्ति प्रबंधन (viii) जोखिम पूँजी (वेंचर केपिटल) (ix) अभिरक्षक सेवाएं (x) फैक्टरिंग (xi) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (xii) लीजिंग तथा वित्त (xiii) आवास वित्त (xiv) फारेक्स ब्रोकिंग (xv) क्रेडिट कार्ड कारोबार (xvi) मुद्रा परिवर्तन कारोबार (xvii) माइक्रो क्रेडिट (xviii) ग्रामीण क्रष्ण 	100%	स्वचालित मार्ग से

एक्स.8.2	अन्य शर्तें		
	<p>(1) निवेश निम्नलिखित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों के अधीन होगा:</p> <p>(i) 51% तक की विदेशी पूंजी के लिए 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे।</p> <p>(ii) 51% से अधिक परंतु 75% तक की विदेशी पूंजी के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे।</p> <p>(iii) 75% से अधिक की विदेशी पूंजी के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें से 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर को प्रारंभिक रूप में लाया जाना होगा और शेष को 24 महीनों के भीतर लाया जाएगा।</p> <p>(iv) एनबीएफसी जिनमें (i) 75% से अधिक तथा 100% तक का विदेशी निवेश है तथा (ii) जिनका न्यूनतम पूंजीकरण 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, वे बिना अतिरिक्त पूंजी लाए और कार्यरत अनुपंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए उप-अनुपंगी संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं। तदनुसार, समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति पर डीआईपीपी के परिपत्र 1 के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त निचले स्तर की अनुपंगी संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।</p> <p>(v) संयुक्त उद्यम द्वारा परिचालित होने वाली एनबीएफसी भी, जिनमें विदेशी निवेश 75% या उससे कम है, अन्य एनबीएफसी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु अनुपंगी संस्थाएं गठित कर सकती हैं, बशर्ते अनुपंगी संस्थाएं उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) तथा निम्नलिखित (vi) में वर्णित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती हों।</p> <p>(vi) गैर निधि आधारित गतिविधियां: विदेशी निवेश के स्तर पर विचार किए बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुमति प्राप्त सभी गैर निधि आधारित एनबीएफसी को 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे:</p> <p>ऐसी किसी कंपनी को किसी अन्य गतिविधि के लिए कोई अनुपंगी संस्था गठित करने और किसी एनबीएफसी होल्डिंग/परिचालन कंपनी की ईक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी: निम्नलिखित गतिविधियों को गैर निधि आधारित गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:</p> <p>(ए) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं</p> <p>(बी) वित्तीय परामर्श</p> <p>(सी) फारेंक्स ब्रोकिंग</p> <p>(डी) मुद्रा परिवर्तन कारोबार</p> <p>(अ) क्रेडिट रेटिंग एंजेंसी</p> <p>(vii) ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे।</p> <p>टिप्पणी : (i) क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान उत्पादों यथा - क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मूल्य वर्धित कार्ड आदि का निर्गमन, बिक्री, विपणन एवं डिजाईनिंग शामिल है।</p> <p>(ii) लीजिंग तथा वित्त में सिर्फ वित्तीय लीज़ को ही शामिल किया जाएगा, परिचालन लीज़ इसमें शामिल नहीं होंगी। परिचालन लीज़ में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।</p> <p>(2) एनबीएफसी को उनसे संबंधित विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यथा लागू, का अनुपालन करना होगा।</p>		
एक्स.3	वाईट लेबल एटीएम परिचालन	100%	स्वचालित
	अन्य शर्तें : <ol style="list-style-type: none"> कोई भी गैर-बैंकिंग एंटीटी, जो वाईट लेबल एटीएम का परिचालन करने की इच्छुक है, के पास उसकी पिछले (बीते) वित्त वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेन्स-शीट के अनुसार कम से कम 100 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति होनी चाहिए और इसे सदैव बनाए रखना चाहिए। यदि कोई एंटीटी एनबीएफसी से जुड़ी 18 गतिविधियों में से किसी कार्य से सम्बद्ध है, तो वाईट लेबल एटीएम का परिचालन करने की इच्छुक ऐसी कंपनी को उपर्युक्त पैरा एक्स.2 में वर्णित एनबीएफसी में विदेशी निवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों का अनुपालन करना होगा। वाईट लेबल एटीएम का परिचालन में किया जाने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारतीय रिजर्व बैंक के समय समय पर यथा शांशोधित परिपत्र सं. DPSS, CO, PD, No. 2298/02.10.002/2011-12 की शर्तों के अधीन होगा। 		
एक्स. 9	पावर एक्सचेंज		

एक.9.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियमावली, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज	49%	स्वचालित मार्ग से
एक.9.2	अन्य शर्तें		
	(i) FII खरीद केवल द्वितीय बाजार तक ही सीमित होगी; (ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था जिनमें मिलकर कार्य कर रहे व्यक्ति भी शामिल हैं, इन कंपनियों की 5% से अधिक इक्कीटी धारित नहीं कर सकेंगे; और (iii) विदेशी निवेश सेवी के विनियमावली, अन्य लागू कानूनों/विनियमनों, सुरक्षा एवं अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे।		
एक.10	पेशन क्षेत्र	49%	26% तक स्वचालित मार्ग से; 6% से 49% तक सरकारी मार्ग से
17.	फार्मास्यूटिकल		
17.1	ग्रीन फील्ड	100%	स्वचालित
17.2	ब्राउन फील्ड	100%	सरकारी
17.3	अन्य शर्तें		
	(i) विशिष्ट परिस्थितियों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन को छोड़कर अन्य मामलों में 'गैर-प्रतिस्पर्धी' खंड/शर्त की अनुमति नहीं होगी। (ii) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता के लिए यह अपेक्षित होगा कि एकआईपीबी आवेदन के साथ उक्त आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। (iii) ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन देते समय सरकार उचित शर्तें लगा सकती हैं।		
	नोट : i. चिकित्सा उपकरणों (डिवाइसेज़) के उत्पादन हेतु स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अतः उल्लिखित शर्तें इस उद्योग के ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी। ii. मेडिकल डिवाइस (उपकरण) अर्थात् :- (ए) विनिर्माता द्वारा अपेक्षित सॉफ्टवेयर सहित कोई भी यंत्र(instrument), उपकरण(apparatus), औज़ार(appliances), इंप्लांट, सामग्री अथवा अन्य वस्तुएँ, जो अकेले अथवा अन्य उपकरणों के साथ मिलकर विशेषतः मनुष्य अथवा पशुओं के लिए निम्नलिखित एक अथवा बहुविध विशिष्ट उद्देश्यों से उपयोग में लाये जाते हों, जैसे :- (एए) किसी बीमारी अथवा विकार की पहचान, रोकथाम, निगरानी, इलाज अथवा राहत के लिए; (एबी) किसी जछम अथवा विकलांगता की पहचान, निगरानी, इलाज, राहत अथवा सहायता के लिए; (एसी) शारीरिक संरचना अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जांच, बदलाव अथवा सुधार अथवा सहायता के लिए; (एडी) जीवन-रक्षा और जान बचाने में सहायक; (एई) मेडिकल उपकरणों का विसंक्रमण; (एएफ) गर्भाधान नियंत्रण एवं ऐसे उपकरण, जो मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर पर / में किसी औषधीय अथवा प्रतिरक्षात्मक और चयापचय के माध्यम से अपनी मूल कार्रवाई के उद्देश्य को सीधे प्राप्त नहीं करते हैं, किन्तु इन माध्यमों के कार्य में सहायक होते हैं; (बी) इस प्रकार के यंत्र, उपकरणों, औज़ारों, सामग्री अथवा वस्तुओं के सहायक उप-साधन; (सी) उपकरण जो अभिकर्मक(regeant), अभिकर्मक-उत्पाद, कैलिब्रेटर (Calibrator), नियंत्रण सामग्री, किट, इनस्ट्रुमेंट, उपकरण(apparatus), औज़ार(appliances) अथवा सिस्टम जो अकेले अथवा किसी अन्य उपकरण के साथ परीक्षण एवं चिकित्सा अथवा निदान के उद्देश्य से सूचना देने के लिए मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर के नमूने (specimens) के विट्रो-परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हों; iii. उपर्युक्त नोट (ii) में दी गई चिकित्सा उपकरण की परिभाषा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन के		

अधीन होगी।			
18.	रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर		
	<p>निम्नलिखित का विनिर्माण, रख-रखाव एवं परिचालन: (i) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से उपनगरीय रेल कोरिडोर, (ii) स्पीड ट्रेन परियोजनाएं, (iii) केवल माल ढुलाई के लिए विशिष्ट लाइनें, (iv) ट्रेन सेटों सहित रोलिंग स्टॉक, और लोकोमोटिव/कोच निर्माण एवं रखरखाव सुविधाएं, (v) रेलवे विद्युतीकरण, (vi) सिग्लिंग सिस्टम, (vii) फ्रेट टर्मिनल, (viii) यात्री टर्मिनल, (ix) औद्योगिक पार्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबन्धित रेलवे लाइनें/सार्विंग सहित विद्युतीकृत रेलवे लाइनें और मुख्य लाइनों से जोड़ने वाली लाइनें, एवं (x) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।</p> <p>नोट :-</p> <p>(i) उल्लिखित गतिविधियों में निवेश रेल मंत्रालय के सेक्टोरल दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी भागीदारी के लिए खुला होगा।</p> <p>(ii) संवेदनशील क्षेत्रों में, 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी द्वारा, मामले –दर- मामले के आधार पर, विचार किया जाएगा।</p>	100%	स्वचालित मार्ग से

ी. अनुसूची 9 में,

(i) पैराग्राफ 4को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है, अर्थात पढ़ा जाएगा :

“4. प्रवेश मार्ग

सीमित देयता भागीदारियों (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

i. स्वचालित मार्ग के तहत जिन क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति हैं ऐसे क्षेत्रों / गतिविधियों से जुड़ी सीमित देयता भागीदारियों (LLP) में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है एवं इसमें एफडीआई से संबंधित पेरफोर्मेंस की शर्तें लागू नहीं हैं।

ii. किसी भारतीय कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी, जिसमें विदेशी निवेश उपलब्ध है, को ऐसी अन्य किसी कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी में निवेश की अनुमति है जो स्वचालित मार्ग के तहत ऐसे क्षेत्रों से संबद्ध है जिनमें में 100% एफडीआई की अनुमति है और इसमें एफडीआई संबंधी परफोर्मेंस की शर्तें लागू नहीं होंगी। उपर्युक्त शर्तों का अनुपान सुनिश्चित करने दायित्व डाउनस्ट्रीम निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी / सीमित देयता भागीदारियों (LLP) पर होगा।

iii. देयता भागीदारियों (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश LLP अधिनियम, 2008 की शर्तों के अधीन होगा।”

ii) अनुसूची 9 में, पैराग्राफ 8 को हटाया गया है।

ई. मौजूदा अनुसूची 11 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः

“अनुसूची 11

[विनियम 5 (10) देखें]

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा निवेश संस्था में निवेश

1. अनिवासी भारतीय (NRI) और आर.एफ.पी.आई (RFPI) सहित भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, इस अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निवेश संस्था की यूनिटों में निवेश कर सकता है।
2. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति अथवा पंजीकृत / निगमित संस्था द्वारा निवेश संस्था के अंजित यूनिटों के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत किए गए आवक विप्रेषण जिसमें NRE अथवा FCNR खाते को नामे करना शामिल है, द्वारा किए जाएंगे।

3. इस अनुसूची के अनुसार भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई यूनिटें सेबी द्वारा निर्मित विनियमों अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बेची अथवा अंतरित अथवा प्रतिदान (redeem) की जा सकेंगी।

4. मूल विनियमावली के विनियम 14 में परिभाषित रूप में यदि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा मैनेजर अथवा निवेश मैनेजर भारतीय 'स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित' न हों, तो ऐसी निवेश संस्था द्वारा किए जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश को विदेशी निवेश माना जाएगा।

बशर्ते कि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा मैनेजर अथवा निवेश मैनेजर जो कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी (LLP) से भिन्न रूप में संगठित हों, के संबंध में सेबी (SEBI) द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा मैनेजर अथवा निवेश मैनेजर विदेशी स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित है।

स्पष्टीकरण 1 : मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में स्वाधिकरण और नियंत्रण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) एक समूहित निवेश संस्था है। अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) का 'नियंत्रण' अन्य सामान्यजनों को छोड़कर 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' के हाथ में होना चाहिए। अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) के 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' यदि व्यक्ति हैं, तो ऐसे मामलों में इन अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) द्वारा किए गए डाउनस्ट्रीम निदेशों को घेरेलू निवेश मानने के लिए उसके 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' निवासी भारतीय होने चाहिए।

स्पष्टीकरण 2 : यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेश संस्था की आधारभूत निधियों (investment in the corpus) में विदेशी निवेश की सीमा यह निर्धारित करने का कारक नहीं होगी कि संबंधित निवेश संस्था द्वारा किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश विदेशी निवेश है अथवा नहीं।

5. किसी निवेश संस्था द्वारा किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश, जिसकी गणना विदेशी निवेश के रूप में की जाती है, वह डाउनस्ट्रीम निवेश जिस कंपनी में किया जाता है, उसके संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अथवा मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के उपबंधों के अनुसार यथा लागू सेक्टोरल कैप और शर्टों/प्रतिबंधों, यदि कोई, हों के अनुरूप होना ही चाहिए।

6. किसी निवेश संस्था द्वारा किसी सीमित देयता भागीदारी (LLP) में किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश जिसकी गणना विदेशी निवेश के रूप में की जाती है, उसे सीमित देयता भागीदारी (LLP) में विदेशी निवेश से संबंधित मूल विनियमावली की अनुसूची 9 में दिए गए उपबंधों के अनुरूप होना चाहिए।

7. अल्टरनेटिव निवेश निधियां श्रेणी ||| केवल उन प्रतिभूतियों अथवा लिखतों में ही पोर्टफोलियो निवेश कर सकती हैं जिनमें मूल विनियमावली के अनुसार कोई पंजीकृत पोर्टफोलियो निवेशक निवेश कर सकता है।

8. विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली निवेश संस्था से अपेक्षित होगा कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में ऐसी रिपोर्ट, समय-समय पर प्रस्तुत करे जैसी कि उनके द्वारा अपेक्षा की जाती है।

[सं. 1/1/ईएम-2016]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. सं.406 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004

सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007

सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007	सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008	सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008	सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009	सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010	सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012	सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012	सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012	सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012	सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013	सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013	सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013	सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013	सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013	सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013	सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013	सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013	सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013	सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013	

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th February, 2016

No.FEMA.362/2016-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2016

G.S.R. 166 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

1. Short Title and Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulation

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000),

(A) In Regulation 2, after clause (viiA) and before the existing clause (viia), the following clause shall be inserted, namely:

“(vii AA) “Manufacture”, with its grammatical variations, means a change in a non-living physical object or article or thing- (a) resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character and use; or (b) bringing into existence of a new and distinct object or article or thing with a different chemical composition or integral structure.”

(B) In Regulation 14,

(a) in sub-regulation 1, the existing clause (i) and clause (ia) shall be amended as under respectively :

“(i) for the purpose of this regulation, the expression ‘ownership and control’ shall mean and include

(a) a company shall be considered as owned by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens. A Limited Liability Partnership will be considered as owned by resident Indian citizens if more than 50% of the investment in such an LLP is contributed by resident Indian citizens and/ or entities which are ultimately ‘owned and controlled by resident Indian citizens’ and such resident Indian citizens and entities have majority of the profit share;

(b) A company owned by non-residents shall mean an Indian company that is not owned by resident Indian citizens.

(ia) ‘Control’ shall include the right to appoint a majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements.

Explanation: For the purpose of Limited Liability Partnership, ‘control’ shall mean right to appoint majority of the designated partners, where such designated partners, with specific exclusions to others, have control over all the policies of Limited Liability Partnership.”

(b) in sub-regulation 3, in clause (iv), the existing sub-clause (D) shall be amended, namely:

“(D) In the I&B sector where the sectoral cap is up to 49%, the company would need to be ‘owned and controlled’ by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned and controlled by resident Indian citizens.

(a) For this purpose, the equity held by the largest Indian shareholder would have to be at least 51 % of the total equity, excluding the equity held by Public Sector Banks and Public Financial Institutions, as defined in Section 4A of the Companies Act, 1956 or Section 2 (72) of the Companies Act, 2013, as the case may be. The term ‘largest Indian shareholder’, used in this clause, will include any or a combination of the following:

(i) In the case of an individual shareholder,

(aa) The individual shareholder,

(bb) A relative of the shareholder within the meaning of Section 2 (77) of Companies Act, 2013.

(cc) A company/group of companies in which the individual shareholder/HUF to which he belongs has management and controlling interest.

(ii) In the case of an Indian company,

(aa) The Indian company

(bb) A group of Indian companies under the same management and ownership control.

(b) For the purpose of this Clause, “Indian company” shall be a company which must have a resident Indian or a relative as defined under Section 2 (77) of Companies Act, 2013/HUF, either singly or in combination holding at least 51% of the shares.

(c) Provided that, in case of a combination of all or any of the entities mentioned in Sub-Clauses (i) and (ii) above, each of the parties shall have entered into a legally binding agreement to act as a single unit in managing the matters of the applicant company.”

(c) The existing sub-regulation 5 shall be amended as under, namely:

“Guidelines for establishment of Indian companies/ transfer of ownership or control of Indian companies, from resident Indian citizens to non-resident entities, in sectors under government approval route

Foreign investment in sectors/activities under government approval route will be subject to government approval where:

- (i) *An Indian company is being established with foreign investment and is not owned by a resident entity or*
- (ii) *An Indian company is being established with foreign investment and is not controlled by a resident entity or*
- (iii) *The control of an existing Indian company, currently owned or controlled by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned or controlled by resident Indian citizens, will be/is being transferred/passed on to a non-resident entity as a consequence of transfer of shares and/or fresh issue of shares to non-resident entities through amalgamation, merger/demerger, acquisition etc. or*
- (iv) *The ownership of an existing Indian company, currently owned or controlled by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned or controlled by resident Indian citizens, will be/is being transferred/passed on to a non-resident entity as a consequence of transfer of shares and/or fresh issue of shares to non-resident entities through amalgamation, merger/demerger acquisition etc.*
- (v) *It is clarified that Foreign investment shall include all types of foreign investments i.e. FDI, investment by FIIs, FPIs, QFIs, NRIs, ADRs, GDRs, Foreign Currency Convertible Bonds (FCCB) and fully, mandatorily & compulsorily convertible preference shares/debentures, regardless of whether the said investments have been made under Schedule 1, 2, 2A, 3, 6, 8, 9 and 10 of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations.*
- (vi) *Investment by NRIs under Schedule 4 of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations, 2000 will be deemed to be domestic investment at par with the investment made by residents.*
- (vii) *A company, trust and partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by non-resident Indians will be eligible for investments under Schedule 4 of FEMA (Transfer or issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations, 2000 and such investment will also be deemed domestic investment at par with the investment made by residents.”*

(d) in sub-regulation 6, the existing clause (ii) shall be amended, namely:

“(ii) Downstream investments by Indian companies/LLPs will be subject to the following conditions:

- a. *Such a company/LLP is to notify SIA, DIPP and FIPB of its downstream investment in the form available at <http://www.fipbindia.com> within 30 days of such investment, even if capital instruments have not been allotted, along with the modality of investment in new/existing ventures (with/without expansion programme);*
- b. *Downstream investment by way of induction of foreign equity in an existing Indian Company to be duly supported by a resolution of the Board of Directors as also a shareholders agreement, if any;*
- c. *Issue/transfer/pricing/valuation of shares shall be in accordance with applicable SEBI/RBI guidelines;*
- d. *For the purpose of downstream investment, the Indian companies/LLPs making the downstream investments would have to bring in requisite funds from abroad and not leverage funds from the domestic market. This would, however, not preclude downstream companies/LLPs, with operations, from raising debt in the domestic market. Downstream investments through internal accruals are permissible (For the purposes of FDI, internal accruals will mean as profits transferred to reserve account after payment of taxes), subject to the provision of clause (i) above and also as elaborated below:*
 - A. *Foreign investment into an Indian company, engaged only in the activity of investing in the capital of other Indian company/ies, will require prior Government/FIPB approval, regardless of the amount or extent of foreign investment. Foreign investment into Non-Banking Finance Companies (NBFCs), carrying on activities approved for FDI, will be subject to the conditions specified in Annex B of Schedule I to these Regulations.*
 - B. *Those companies, which are Core Investment Companies (CICs), will have to additional follow RBI's Regulatory Framework for CICs.*
 - C. *For undertaking activities which are under automatic route and without FDI linked performance conditions, Indian company which does not have any operations and also does not have any downstream investments, will be permitted to have infusion of foreign investment under automatic route. However, approval of the Government will be required for such*

companies for infusion of foreign investment for undertaking activities which are under Government route, regardless of the amount or extent of foreign investment. Further, as and when such a company commences business(s) or makes downstream investment, it will have to comply with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps.

Note: Foreign investment into other Indian companies would be in accordance/compliance with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps;

e) *The FDI recipient Indian company at the first level which is responsible for ensuring compliance with the FDI conditionalities like no indirect foreign investment in prohibited sector, entry route, sectoral cap / conditionalities, etc. for the downstream investment made by in the subsidiary companies at second level and so on and so forth would obtain a certificate to this effect from its statutory auditor on an annual basis as regards status of compliance with the instructions on downstream investment and compliance with FEMA provisions. The fact that statutory auditor has certified that the company is in compliance with the regulations as regards downstream investment and other FEMA prescriptions will be duly mentioned in the Director's report in the Annual Report of the Indian company. In case statutory auditor has given a qualified report, the same shall be immediately brought to the notice of the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department (FED), Regional Office (RO) of the Reserve Bank in whose jurisdiction the Registered Office of the company is located and shall also obtain acknowledgement from the RO of having intimated it of the qualified auditor report. RO shall file the action taken report to the Chief General Manager-in-Charge, Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai 400001."*

C In Schedule 1,

(i) In paragraph 2, paragraph beginning with “Provided further that the shares or convertible debentures.....” and ending with “.....permitted to the extent specified in Regulation 14.” shall be deleted.

(ii) *in paragraph 2, in sub-paragraph 4, after clause (iv), the following shall be added, namely:*

“(v) by way of swap of shares, provided the company in which the investment is made is engaged in an automatic route sector, subject to the condition that irrespective of the amount, valuation of the shares involved in the swap arrangement will have to be made by a Merchant Banker registered with SEBI or an Investment Banker outside India registered with the appropriate regulatory authority in the host country.

Note: A company engaged in a sector where foreign investment requires Government approval may issue shares to a non-resident through swap of shares only with approval of the Government”

(iii) *in paragraph 3, the existing sub-paragraph (c) shall stands deleted.*

(iv) *in ‘Annex B’, the existing table shall be substituted with the following, namely:*

Foreign Investments caps and entry route in various sectors

SL.No	Sector/Activity	Foreign Investment Cap (%)	Entry Route
Agriculture			
1.	Agriculture & Animal Husbandry		
	a) Floriculture, horticulture, Apiculture and Cultivation Of vegetables & mushrooms under controlled conditions; b) Development and production of seeds and planting material; c) Animal Husbandry (including breeding of dogs), Pisiculture, Aquaculture, under controlled conditions; and d) Services related to agro and allied sectors. Note :Besides the above, FDI is not allowed in any other agricultural sector/activity	100%	Automatic
1.1	Other Conditions		

	<p>The term 'under controlled conditions' covers the following:</p> <p>(i) 'Cultivation under controlled conditions' for the categories of floriculture, horticulture, cultivation of vegetables and mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically</p> <p>(ii) In case of Animal Husbandry, scope of the term 'under controlled conditions' covers –</p> <p>(a) Rearing of animals under intensive farming systems with stall- feeding. Intensive farming system will require climate systems (ventilation, temperature/humidity management), health care and nutrition, herd registering/pedigree recording, use of machinery, waste management systems as prescribed by the National Livestock Policy 2013 and in conformity with the existing 'Standard Operating Practices and Minimum Standard Protocol.'</p> <p>(b) Poultry breeding farms and hatcheries where micro-climate is controlled through advanced technologies like incubators, ventilation systems etc.</p> <p>(iii) In the case of pisciculture and aquaculture, scope of the term 'under controlled conditions' covers –</p> <p>(a) Aquariums</p> <p>(b) Hatcheries where eggs are artificially fertilized and fry are hatched and incubated in an enclosed environment with artificial climate control.</p> <p>(iv) In the case of apiculture, scope of the term 'under controlled conditions' covers –</p> <p>a) Production of honey by bee-keeping, except in forest/wild, in designated spaces with control of temperatures and climatic factors like humidity and artificial feeding during lean seasons.</p>		
2.	Plantation		
2.1	i. Tea sector including tea plantations ii. Coffee plantations iii. Rubber Plantations iv. Cardamom plantations v. Palm oil tree plantations vi. Olive oil tree plantations <p style="text-align: center;">Note: FDI is not allowed in any plantation sector/activity except those mentioned above.</p>	100%	Automatic route
2.2	Other Condition		
	Prior approval of the State Government concerned is required in case of any future land use change.		
3.	MINING		
3.1	Mining and Exploration of metal and non-metal ores including diamond, gold, silver and precious ores but excluding titanium bearing minerals and its ores; subject to the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.	100%	Automatic
3.2	Coal and Lignite		
	(1) Coal & Lignite mining for captive consumption by power projects, iron & steel and cement units and other eligible activities permitted under and subject to the provisions of Coal Mines (Nationalization) Act, 1973.	100%	Automatic
	(2) Setting up coal processing plants like washeries, subject to the condition that the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing.	100%	Automatic
3.3	Mining and mineral separation of titanium bearing minerals and ores, its value addition and integrated activities		
3.3.1	Mining and mineral separation of titanium bearing minerals & ores, its value addition and integrated activities subject to sectoral regulations and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.	100%	Government

3.3.2	Other Conditions		
	<p>(i) FDI for separation of titanium bearing minerals & ores will be subject to the following conditions viz:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Value addition facilities are set up within India along with transfer of technology; B. Disposal of tailings during the mineral separation shall be carried out in accordance with regulations framed by the Atomic Energy Regulatory Board such as Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987. <p>(ii) FDI will not be allowed in mining of "prescribed substances" listed in the Notification No. S.O. 61(E), dated 18.1.2006, issued by the Department of Atomic Energy.</p>		
	Clarification:		
	<ul style="list-style-type: none"> i. For titanium bearing ores such as Ilmenite, Leucoxene and Rutile, manufacture of titanium dioxide pigment and titanium sponge constitutes value addition, Ilmenite can be processed to produce Synthetic Rutile or Titanium Slag as an intermediate value added product. ii. The objective is to ensure that the raw material available in the country is utilized for setting up downstream industries and the technology available internationally is also made available for setting up such industries within the country. Thus, if with the technology transfer, the objective of the FDI Policy can be achieved, the conditions prescribed at (i) (A) above shall be deemed to be fulfilled. 		
4.	Petroleum & Natural Gas		
4.1	Exploration activities of oil and natural gas fields, infrastructure related to marketing of petroleum products and natural gas, marketing of natural gas and petroleum products, petroleum product pipelines, natural gas/pipelines, LNG Regasification infrastructure, market study and formulation and Petroleum refining in the private sector, subject to the existing sectoral policy and regulatory framework in the oil marketing sector and the policy of the Government on private participation in exploration of oil and the discovered fields of national oil companies.	100%	Automatic
4.2	Petroleum refining by the Public Sector Undertakings (PSUs), without any disinvestment or dilution of domestic equity in the existing PSUs.	49%	Automatic
5	Manufacturing	100%	Automatic
	Subject to the provisions of the FDI policy, foreign investment in 'manufacturing' sector is under automatic route. Further, a manufacturer is permitted to sell its products manufactured in India through wholesale and/or retail, including through e-commerce without Government approval.		
6.	Defence		
6.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951	49%	Government route up to 49% Above 49% under Government route on case to case basis, wherever it is likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country.
6.2	Other Conditions		
	<ul style="list-style-type: none"> i. Infusion of fresh foreign investment within the permitted automatic route level, in a company not seeking industrial license, resulting in change in the ownership pattern or transfer of stake by existing investor to new foreign investor, will require Government approval. ii. Licence applications will be considered and licences given by the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, in consultation with Ministry of Defence and Ministry of External Affairs. iii. Foreign investment in the sector is subject to security clearance and guidelines of the M/o Defence. iv. Investee company should be structured to be self-sufficient in areas of product design and development. The investee/joint venture company along with manufacturing facility, should also have maintenance and life cycle support facility of the product being manufactured in India. 		

Services Sector			
Information Services			
7.	Broadcasting		
7.1	Broadcasting Carriage Services		
7.1.1	(1) Teleports (setting up of up-linking HUBs/Teleports); (2) Direct to Home (DTH); (3) Cable Networks [Multi System Operators (MSOs) operating at National or State or District level and undertaking up gradation of networks towards digitalization and addressability]; (4) Mobile TV; (5) Headend-in-the Sky Broadcasting Service (HITS)	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49%
7.1.2	Cable Networks (Other MSOs not undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability and Local Cable Operators (LCOs)).	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49%
7.2	Broadcasting Content Services		
7.2.1	Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio) , subject to such terms and conditions, as specified from time to time, by Ministry of Information & Broadcasting, for grant of permission for setting up of FM Radio stations.	49%	Government
7.2.2	Up-Linking of 'News & Current Affairs' TV Channels	49%	Government
7.2.3	Up-linking a Non-'News & Current Affairs' TV Channels/Down-linking of TV Channels	100%	Automatic
7.3	FDI for Up-linking/Down-linking TV Channels will be subject to compliance with the relevant Up-linking/Down-linking Policy notified by the Ministry of Information & Broadcasting from time to time.		
7.4	Foreign Investment (FI) in companies engaged in all the aforestated services will be subject to relevant regulations and such terms and conditions, as may be specified from time to time, by the Ministry of Information and Broadcasting.		
7.5	The foreign investment (FI) limit in companies engaged in the afore stated activities shall include, in addition to FDI, investment by Foreign Institutional Investors (FIIs), Foreign Portfolio Investors(FPIs), Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs), [Depository Receipts issued under Schedule 10 of these Regulations with equity shares or compulsorily and mandatorily convertible preference shares or compulsory and mandatorily convertible debentures or warrant or any other security in which foreign direct investment can be made in terms of Schedule 1 of the principal Regulations, as underlying] (GDRs) and convertible preference shares held by foreign entities.]		
7.6	Foreign investment in the aforestated broadcasting carriage services will be subject to the following security conditions/ terms: Mandatory Requirement for Key Executives of the Company (i) The majority of Directors on the Board of the Company shall be Indian Citizens. (ii) The Chief Executive Officer (CEO), Chief Officer In-charge of technical network operations and Chief Security Officer should be resident Indian citizens Security Clearance of Personnel (iii) The Company, all Directors on the Board of Directors and such key executives like Managing Director/ Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), shareholders who individually hold 10% or more paid-up capital in the company and any other category, as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time, shall require to be security cleared.		

	<p>In case of the appointment of Directors on the Board of the Company and such key executives like Managing Director/Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), etc., as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time, prior permission of the Ministry of Information and Broadcasting shall have to be obtained.</p> <p>It shall be obligatory on the part of the company to also take prior permission from the Ministry of Information and Broadcasting before effecting any change in the Board of Directors.</p> <p>(iv) The Company shall be required to obtain security clearance of all foreign personnel likely to be deployed for more than 60 days in a year by way of appointment, contract, and consultancy or in any other capacity for installation, maintenance, operation or any other services prior to their deployment. The security clearance shall be required to be obtained every two years.</p> <p>Permission vis-a-vis Security Clearance</p> <p>(v) The permission shall be subject to permission holder/licensee remaining security cleared throughout the currency of permission. In case the security clearance is withdrawn the permission granted is liable to be terminated forthwith.</p> <p>(vi) In the event of security clearance of any of the persons associated with the permission holder/licensee or foreign personnel being denied or withdrawn for any reasons whatsoever, the permission holder/licensee will ensure that the concerned person resigns or his services terminated forthwith after receiving such directives from the Government, failing which the permission/license granted shall be revoked and the company shall be disqualified to hold any such Permission/license in future for a period of five years.</p> <p>Infrastructure/Network/Software related requirement</p> <p>(vii) The officers/officials of the licensee companies dealing with the lawful interception of Services will be resident Indian citizens.</p> <p>(viii) Details of infrastructure/ network diagram (technical details of the network) could be provided on a need basis only, to equipment suppliers/manufactures and the affiliate of the licensee company. Clearance from the licensor would be required if such information is to be provided to anybody else.</p> <p>(ix) The Company shall not transfer the subscribers' databases to any person/place outside India unless permitted by relevant Law.</p> <p>(x) The Company must provide traceable identity of their subscribers.</p> <p>Monitoring, Inspection and Submission of Information</p> <p>(xi) The Company should ensure that necessary provision (hardware/software) is available in their equipment for doing the Lawful interception and monitoring from a centralized location as and when required by Government.</p> <p>(xii) The company, at its own costs, shall, on demand by the Government or its authorized representative, provide the necessary equipment, services and facilities at designated place(s) for continuous monitoring or the broadcasting service by or under supervision of the Government or its authorized representative.</p> <p>(xiii) The Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative shall have the right to inspect the broadcasting facilities. No prior permission/intimation shall be required to exercise the right of Government or its authorized representative to carry out the inspection. The company will, if required by the Government or its authorized representative, provide necessary facilities for continuous monitoring for any particular aspect of the company's activities and operations. Continuous monitoring, however, will be confined only to security related aspects, including screening of objectionable content.</p> <p>(xiv) The inspection will ordinarily be carried out by the Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative after reasonable notice, except in circumstances where giving such a notice will defeat the very purpose of the inspection.</p> <p>(xv) The company shall submit such information with respect to its services as may be required by the Government or its authorized representative, in the format as may be required, from time to time.</p> <p>(xvi) The permission holder/licensee shall be liable to furnish the Government of India or its authorized representative or TRAI or its authorized representative, such reports, accounts, estimates, returns or such other relevant information and at such periodic intervals or such times as may be required.</p> <p>The service providers should familiarize/train designated officials of the Government or officials of TRAI or its authorized representative(s) in respect of relevant operations/features of their systems.</p> <p>National Security Conditions</p> <p>(xvii) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee Company from operating in any sensitive area from the National Security angle. The Government of India, Ministry of Information and Broadcasting shall have the right to temporarily suspend the permission of the permission</p>
--	---

	<p>holder/Licensee in public interest or for national security for such period or periods as it may direct. The company shall immediately comply with any directives issued in this regard failing which the permission issued shall be revoked and the company disqualified to hold any such permission, in future, for a period of five years.</p> <p>(xviii) The company shall not import or utilize any equipment, which are identified as unlawful and/or render network security vulnerable.</p> <p>Other conditions</p> <p>(xix) Licensor reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest or for proper provision of broadcasting services.</p> <p>(xx) Licensee will ensure that broadcasting service installation carried out by it should not become a safety hazard and is not in contravention of any statute, rule or regulation and public policy.</p>	
8.	Print Media	
8.1	Publishing of newspaper and periodicals dealing with news and current affairs	26%
8.2	Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs	26%
8.2.1	Other conditions	
	<p>(i) 'Magazine', for the purpose of these guidelines, will be defined as a periodical publication, brought out on non-daily basis, containing public news or comments on public news.</p> <p>(ii) Foreign investment would also be subject to the Guidelines for Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs issued by the Ministry of Information & Broadcasting on 4-12-2008.</p>	
8.3	Publishing/printing of Scientific and Technical Magazines/ specialty journals/periodicals, subject to compliance with the legal framework as applicable and guidelines issued in this regard from time to time by Ministry of Information and Broadcasting.	100%
8.4	Publication of facsimile edition of foreign newspapers	100%
8.4.1	Other conditions:	
	<p>(i) FDI should be made by the owner of the original foreign newspapers whose facsimile edition is proposed to be brought out in India.</p> <p>(ii) Publication of facsimile edition of foreign newspapers can be undertaken only by an entity incorporated or registered in India under the provisions of the Companies Act, as applicable.</p> <p>(iii) Publication of facsimile edition of foreign newspaper would also be subject to the Guidelines for publication of newspapers and periodicals dealing with news and current affairs and publication of facsimile edition of foreign newspapers issued by Ministry of Information & Broadcasting on 31-3-2006, as amended from time to time.</p>	
9.	Civil Aviation	
9.1	<p>The Civil Aviation sector includes Airports, Scheduled and Non-Scheduled domestic passenger airlines, Helicopter services/Seaplane services, Ground Handling Services, Maintenance and Repair organizations; Flying training institutes; and Technical training institutions.</p> <p>For the purposes of the Civil Aviation sector:</p> <p>(i) "Airport" means a landing and taking off area for aircrafts, usually with runways and aircraft maintenance and passenger facilities and includes aerodrome as defined in clause (2) of section 2 of the Aircraft Act, 1934;</p> <p>(ii) "Aerodrome" means any definite or limited ground or water area intended to be used, either wholly or in part, for the landing or departure of aircraft, and includes all buildings, sheds, vessels, piers and other structures thereon or pertaining thereto;</p> <p>(iii) "Air transport service" means a service for the transport by air of persons, mails or any other thing, animate or inanimate, for any kind of remuneration whatsoever, whether such service consists of a single flight or series of flights;</p> <p>(iv) "Air Transport Undertaking" means an undertaking whose business includes the carriage by air of passengers or cargo for hire or reward;</p> <p>(v) "Aircraft component" means any part, the soundness and correct functioning of which, when fitted to an aircraft, is essential to the continued airworthiness or safety of the aircraft and includes any item of equipment;</p> <p>(vi) "Helicopter" means a heavier than air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more power driven rotors on substantially vertical axis;</p> <p>(vii) "Scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, each flight being open to use by members of the</p>	

	public;		
	(viii) "Non-Scheduled air Transport service" means any service which is not a scheduled air transport service and will include Cargo airlines;		
	(ix) "Cargo airlines" would mean such airlines which meet the conditions as given in the Civil Aviation Requirements issued by the Ministry of Civil Aviation;		
	(x) "Seaplane" means an aeroplane capable normally of taking off from and alighting solely on water;		
	(xi) "Ground Handling" means (i) ramp handling, (ii) traffic handling both of which shall include the activities as specified by the Ministry of Civil Aviation through the Aeronautical Information Circulars from time to time, and (iii) any other activity specified by the Central Government to be a part of either ramp handling or traffic handling.		
9.2	Airports		
	(a) Greenfield projects (b) Existing projects	100% 100%	Automatic Automatic upto 74% ; Government Route beyond 74%
9.3	Air Transport Services		
	1) (a) Scheduled Air Transport Service/Domestic Scheduled Passenger Airline (b) Regional Air Transport Service	49% (100% for NRIs)	Automatic
	(2) Non-Scheduled Air Transport Service	100 %	Automatic
	(3) Helicopter services/ seaplane services requiring DGCA approval	100%	Automatic
9.3.1	Other Conditions		
	(a) Air Transport Services would include Domestic Scheduled Passenger Airlines; Non-Scheduled Air Transport Services, helicopter and seaplane services. (b) Foreign airlines are allowed to participate in the equity of companies operating Cargo airlines, helicopter and seaplane services, as per the limits and entry routes mentioned above. (c) Foreign airlines are also allowed to invest in the capital of Indian companies, operating scheduled and non-scheduled air transport services, up to the limit of 49% of their paid-up capital. Such investment would be subject to the following conditions: (i) It would be made under the Government approval route. (ii) The 49% limit will subsume FDI and FII/FPI investment. (iii) The investments so made would need to comply with the relevant regulations of SEBI, such as the Issue of Capital and Disclosure Requirements (ICDR) Regulations/ Substantial Acquisition of Shares and Takeovers (SAST) Regulations, as well as other applicable rules and regulations. (iv) A Scheduled Operator's Permit can be granted only to a company: a) <i>that is registered and has its principal place of business within India;</i> b) <i>the Chairman and at least two-thirds of the Directors of which are citizens of India; and</i> c) <i>the substantial ownership and effective control of which is vested in Indian nationals.</i> (v) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non-scheduled air transport services, as a result of such investment shall be cleared from security view point before deployment; and (vi) All technical equipment that might be imported into India as a result of such investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation. Note: (i) The FDI limits/entry routes, mentioned at paragraph 9.3.1 and 9.3.2 above, are applicable in the situation where there is no investment by foreign airlines. (ii) The dispensation for NRIs regarding FDI up to 100% will also continue in respect of the investment regime specified at paragraph 9.3.1(c) (ii) above. (iii) The policy mentioned at 9.3.1(c) above is not applicable to M/s Air India Limited	49% (100% for NRIs)	Government
9.3.2	Foreign Airlines in the capital of the Indian companies, operating schedule and non-scheduled air transport services	49% (100% for NRIs)	Government
9.4	Other Services under Civil Aviation sector		
	(1) Ground Handling Services subject to sectoral regulations and security clearance	100 %	Automatic

	(2) Maintenance and Repair organizations; flying training institutes and technical training institutions	100%	Automatic
10.	Courier services for carrying packages, parcels and other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act, 1898 and excluding the activity relating to the distribution of letters	100%	Automatic
11.	Construction Development: Townships, Housing, Built-up infrastructure		
11.1	Construction-development projects (which would include development of townships, construction of residential/commercial premises, roads or bridges, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships)	100%	Automatic
11.2	<p>Each phase of the construction development project would be considered as a separate project for the purposes of FDI policy. Investment will be subject to the following conditions:</p> <p>(A) (i) The investor will be permitted to exit on completion of the project or after development of trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage. (ii) Notwithstanding anything contained at (A) (i) above, a foreign investor will be permitted to exit and repatriate foreign investment before the completion of project under automatic route, provided that a lock-in-period of three years, calculated with reference to each tranche of foreign investment has been completed. Further, transfer of stake from one non-resident to another non-resident, without repatriation of investment will neither be subject to any lock-in period nor to any government approval.</p> <p>(B) The project shall conform to the norms and standards, including land use requirements and provision of community amenities and common facilities, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned.</p> <p>(C) The Indian investee company will be permitted to sell only developed plots. For the purposes of this policy "developed plots" will mean plots where trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage, have been made available.</p> <p>(D) The Indian investee company shall be responsible for obtaining all necessary approvals, including those of the building/layout plans, developing internal and peripheral areas and other infrastructure facilities, payment of development, external development and other charges and complying with all other requirements as prescribed under applicable rules/byelaws/regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned.</p> <p>(E) The State Government/Municipal/Local Body concerned, which approves the building/development plans, will monitor compliance of the above conditions by the developer.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. It is clarified that FDI is not permitted in an entity which is engaged or proposes to engage in real estate business, construction of farm houses and trading in transferable development rights (TDRs). "Real estate business" means dealing in land and immovable property with a view to earning profit therefrom and does not include development of townships, construction of residential commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships. Further, earning of rent income on lease of the property, not amounting to transfer, will not amount to real estate business. ii. Condition of lock-in period at (A) above will not apply to Hotels &Tourist Resorts, Hospitals, Special Economic Zones (SEZs), Educational Institutions, Old Age Homes and investment by NRIs. iii. Completion of the project will be determined as per the local bye-laws/rules and other regulations of State Governments. iv. It is clarified that 100 % FDI under automatic route is permitted in completed projects for operation and management of townships, malls/ shopping complexes and business centres. Consequent to foreign investment, transfer of ownership and/or control of the investee company from residents to non-residents is also permitted. However, there would be a lock-in-period of three years, calculated with reference to each tranche of FDI, and transfer of immovable property or part thereof is not permitted during this period. 		

	v. "Transfer", in relation to FDI policy on the sector, includes,- a. the sale, exchange or relinquishment of the asset; or b. the extinguishment of any rights therein; or c. the compulsory acquisition thereof under any law; or d. any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) ; or e. any transaction, by acquiring shares in a company or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever, which has the effect of transferring, or enabling the enjoyment of, any immovable property.		
12.	Industrial Parks -New and existing	100%	Automatic
12.1	(i) "Industrial Park" is a project in which quality infrastructure in the form of plots of developed land or built up space or a combination with common facilities, is developed and made available to all the allottee units for the purposes of industrial activity. (ii) "Infrastructure" refers to facilities required for functioning of units located in the Industrial Park and includes roads (including approach roads), railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air conditioning. (iii) "Common Facilities" refer to the facilities available for all the units located in the industrial park, and include facilities of power, roads (including approach roads), railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment, common testing, telecom services, air conditioning, common facility buildings, industrial canteens, convention/conference halls, parking, travel desks, security service, first aid center, ambulance and other safety services, training facilities and such other facilities meant for common use of the units located in the Industrial Park. (iv) "Allocable area" in the Industrial Park means- (a) in the case of plots of developed land - the net site area available for allocation to the units, excluding the area for common facilities. (b) in the case of built up space - the floor area and built-up space utilized for providing common facilities. (c) in the case of a combination of developed land and built-up space - the net site and floor area available for allocation to the units excluding the site area and built-up space utilized for providing common facilities. (v) "Industrial Activity" means manufacturing; electricity; gas and water supply; post and telecommunications; software publishing, consultancy and supply; data processing, database activities and distribution of electronic content; other computer related activities; basic and applied R&D on biotechnology, pharmaceutical sciences/life sciences, natural sciences and engineering; business and management consultancy activities; and architectural, engineering and other technical activities.		
12.2	FDI in Industrial Parks would not be subject to the conditionalities applicable for construction development projects etc. spelt out in para 11 above, provided the Industrial Parks meet with the under-mentioned conditions: (i) it would comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area; (ii) the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total allocable area.		
13.	Satellites - Establishment and operation		
13.1	Satellites Establishment and operation, subject to the sectoral guidelines of Department of Space/ISRO	100%	Government
14.	Private Security Agencies	49%	Government
15.	Telecom services (including Telecom Infrastructure Providers Category-I) All telecom services including Telecom Infrastructure Providers Category-I, viz. Basic, Cellular, United Access Services, Unified license (Access services), Unified License, National/ International Long Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services	100%	Automatic upto 49% Government route beyond 49%

	(GMPCS), All types of ISP licenses, Voice Mail/Audiotex / UMS, Resale of IPLC, Mobile Number Portability services, Infrastructure Provider Category-I (providing dark fibre, right of way, duct space, tower) except Other Service Providers.		
15.1.1	Other Condition		
	FDI up to 100% with 49% on the automatic route and beyond 49% on the government route subject to observance of licensing and security conditions by licensee as well as investors as notified by the Department of Telecommunications (DoT) from time to time, except “Other Service Providers”, which are allowed 100% FDI on the automatic route.		
16.	Trading		
16.1	(i) Cash & Carry Wholesale Trading/Wholesale Trading (including sourcing from MSEs)	100%	Automatic
16.1.1	Definition: Cash & Carry Wholesale trading/Wholesale trading, would mean sale of goods/merchandise to retailers, industrial, commercial, institutional or other professional business users or to other wholesalers and related subordinated service providers. Wholesale trading would, accordingly, imply sales for the purpose of trade, business and profession, as opposed to sales for the purpose of personal consumption. The yardstick to determine whether the sale is wholesale or not would be the type of customers to whom the sale is made and not the size and volume of sales. Wholesale trading would include resale, processing and thereafter sale, bulk imports with ex-port/ ex-bonded warehouse business sales and B2B e-Commerce.		
16.1.2	<p>Guidelines for Cash & Carry Wholesale Trading/Wholesale Trading (WT):</p> <p>(a) For undertaking 'WT', requisite licenses/registration/permits, as specified under the relevant Acts/Regulations/Rules/Orders of the State Government/Government Body/Government Authority / Local Self-Government Body under that State Government should be obtained.</p> <p>(b) Except in case of sales to Government, sales made by the wholesaler would be considered as 'cash & carry wholesale trading/wholesale trading' with valid business customers, only when WT are made to the following entities:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Entities holding sales tax/VAT registration/service tax/excise duty registration; or (ii) Entities holding trade licenses i.e. a license/registration certificate/membership certificate/registration under Shops and Establishment Act, issued by a Government Authority/Government Body/ Local Self-Government Authority, reflecting that the entity/person holding the license/registration certificate/membership certificate, as the case may be, is itself/himself/herself engaged in a business involving commercial activity; or (iii) Entities holding permits/license etc. for undertaking retail trade (like tehbazari and similar license for hawkers) from Government Authorities/Local Self Government Bodies; or (iv) Institutions having certificate of incorporation or registration as a society or registration as public trust for their self consumption. <p>Note: An Entity, to whom WT is made, may fulfil anyone of the 4 conditions.</p> <p>(c) Full records indicating all the details of such sales like name of entity, kind of entity, registration/ license/permit etc. number, amount of sale etc. should be maintained on a day to day basis.</p> <p>(d) WT of goods would be permitted among companies of the same group. However, such WT to group companies taken together should not exceed 25% of the total turnover of the wholesale venture.</p> <p>(e) WT can be undertaken as per normal business practice, including extending credit facilities subject to applicable regulations.</p> <p>(f) A wholesale/cash & carry trader can undertake single brand retail trading, subject to the conditions mentioned in para 16.3. An entity undertaking wholesale/cash and carry as well as retail business will be mandated to maintain separate books of accounts for these two arms of the business and duly audited by the statutory auditors. Conditions of the FDI policy for wholesale/cash and carry business and for retail business have to be separately complied with by the respective business arms.</p>		
16.2	B2B E-commerce activities	100%	Automatic
	E-commerce activities refer to the activity of buying and selling by a company through the e-commerce platform. Such companies would engage only in Business to Business (B2B) e-commerce and not in retail trading, inter alia implying that existing restrictions on FDI in domestic trading would be applicable to e-commerce as well.		
16.3	Single Brand product retail trading	100%	Automatic up to 49%. Government route beyond 49%

	<p>1) Foreign Investment in Single Brand product retail trading is aimed at attracting investments in production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India, and enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global designs, technologies and management practices.</p> <p>2) FDI in Single Brand product retail trading would be subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> Products to be sold should be of a 'Single Brand' only. Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India. 'Single Brand' product-retail trading would cover only products which are branded during manufacturing. A non-resident entity or entities, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake 'single brand' product retail trading in the country for the specific brand, directly or through a legally tenable agreement with the brand owner for undertaking single brand product retail trading. The onus for ensuring compliance with this condition will rest with the Indian entity carrying out single-brand product retail trading in India. The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing/franchise/sub-liscence agreement, specifically indicating compliance with the above condition. The requisite evidence should be filed with the RBI for the automatic route and SIA/FIPB for cases involving approval. In respect of proposals involving FDI beyond 51%, sourcing of 30 of the value of goods purchased, will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen, in all sectors. The quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts which the company will be required to maintain. This procurement requirement would have to be met annually from the commencement of the business i.e. opening of the first store. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of Foreign Investment for the purpose of carrying out single-brand product retail trading. Subject to the conditions mentioned in this Para, a single brand retail trading entity operating through brick and mortar stores, is permitted to undertake retail trading through e-commerce. <p>3) Application seeking permission of the Government for FDI exceeding 49 in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India would be made to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & Promotion. The applications would specifically indicate the product/product categories which are proposed to be sold under a 'Single Brand'. Any addition to the product/product categories to be sold under 'Single Brand' would require a fresh approval of the Government. In case of FDI up to 49 %, the list of products/product categories proposed to be sold except food products would be provided to the RBI.</p> <p>4) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.</p> <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conditions mentioned at Para (2) (b) & (2) (d) will not be applicable for undertaking SBRT of Indian brands. An Indian manufacturer is permitted to sell its own branded products in any manner i.e. wholesale, retail, including through e-commerce platforms. Indian manufacturer would be the investee company, which is the owner of the Indian brand and which manufactures in India, in terms of value, at least 70% of its products in house, and sources, at most 30% from Indian manufacturers. Indian brands should be owned and controlled by resident Indian citizens and/or companies which are owned and controlled by resident Indian citizens. Government may relax sourcing norms for entities undertaking single brand retail trading of products having 'state-of-art' and 'cutting-edge' technology and where local sourcing is not possible. 		
16.4	Multi Brand Retail Trading	51%	Government
	<p>(1) FDI in multi brand retail trading, in all products, will be permitted, subject to the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fresh agricultural produce, including fruits, vegetables, flowers, grains, pulses, fresh poultry, fishery and meat products, may be unbranded. Minimum amount to be brought in, as FDI, by the foreign investor, would be US \$ 100 million. At least 50% of total FDI brought in the first tranche of US \$ 100 million, shall be invested in 'back-end infrastructure' within three years, where 'back-end infrastructure' will include capital expenditure on all activities, excluding that on front-end units; for instance, back-end infrastructure will include investment made towards processing, manufacturing, distribution, design improvement, 		

	<p>quality control, packaging, logistics, storage, warehouse, agriculture market produce infrastructure etc. Expenditure on land cost and rentals, if any, will not be counted for purposes of back-end infrastructure. Subsequent investment in the back-end infrastructure would be made by the MBRT retailer as needed, depending upon its business requirements.</p> <p>(iv) At least 30% of the value of procurement of manufactured/processed products purchased shall be sourced from Indian micro, small and medium industries, which have a total investment in plant & machinery not exceeding US \$ 2.00 million. This valuation refers to the value at the time of installation, without providing for depreciation. The 'small industry' status would be reckoned only at the time of first engagement with the retailer and such industry shall continue to qualify as a 'small industry' for this purpose, even if it outgrows the said investment of US \$ 2.00 million during the course of its relationship with the said retailer. Sourcing from agricultural co-operatives and farmers co-operatives would also be considered in this category. The procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years total value of the manufactured/processed products purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis.</p> <p>(v) Self-certification by the company, to ensure compliance of the conditions at serial Nos. (i), (ii) and (iv) above, which could be cross-checked, as and when required. Accordingly, the investors shall maintain accounts, duly certified by statutory auditors.</p> <p>(vi) Retail sales outlets may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per the 2011 Census or any other cities as per the decision of the respective State Governments, and may also cover an area of 10 kms. Around the municipal/urban agglomeration limits of such cities; retail locations will be restricted to conforming areas as per the Master/Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking.</p> <p>(vii) Government will have the first right to procurement of agricultural products.</p> <p>(viii) The above policy is an enabling policy only and the State Governments/Union Territories would be free to take their own decisions in regard to implementation of the policy. Therefore, retail sales outlets may be set up in those States/Union Territories which have agreed, or agree in future, to allow FDI in MBRT under this policy. The list of States/Union Territories which have conveyed their agreement is at (2) below. Such agreement, in future, to permit establishment of retail outlets under this policy, would be conveyed to the Government of India through the Department of Industrial Policy & Promotion and additions would be made to the list at (2) below accordingly. The establishment of the retail sales outlets will be in compliance of applicable State/Union Territory laws/ regulations, such as the Shops and Establishments Act etc.</p> <p>(ix) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible, for companies with FDI, engaged in the activity of multi-brand retail trading.</p> <p>(x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.</p> <p>(2) List of States/Union Territories as mentioned in Paragraph 16.4.(1) (viii)</p> <p>1. Andhra Pradesh 2. Assam 3. Delhi 4. Haryana 5. Himachal Pradesh 6. Jammu & Kashmir 7. Karnataka 8. Maharashtra 9. Manipur 10. Rajasthan 11. Uttarakhand 12. Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli (Union Territories)</p>		
16.5	Duty Free Shops	100%	Automatic
	<p>(i) Duty Free Shops would mean shops set up in custom bonded area at International Airports/ International Seaports and Land Custom Stations where there is transit of international passengers.</p> <p>(ii) Foreign investment in Duty Free Shops is subject to compliance of conditions stipulated under the Customs Act, 1962 and other laws, rules and regulations.</p> <p>(iii) Duty Free Shop entity shall not engage into any retail trading activity in the Domestic Tariff Area of the country.</p>		
	<p>FINANCIAL SERVICES</p> <p>Foreign investment in other financial services, other than those indicated below, would require prior approval of the Government:</p>		

F.1	Asset Reconstruction Companies		
F.1.1	‘Asset Reconstruction Company’ (ARC) means a company registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act).	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49%
F.1.1.2	<p>Other Conditions</p> <p>(i) Persons resident outside India can invest in the capital of Asset Reconstruction Companies (ARCs) registered with Reserve Bank, up to 49% on the automatic route, and beyond 49% on the Government route.</p> <p>(ii) No sponsor may hold more than 50% of the shareholding in an ARC either by way of FDI or by routing it through an FII/FPI controlled by the single sponsor.</p> <p>(iii) The total shareholding of an individual FII/FPI shall be below 10% of the total paid-up capital.</p> <p>(iv) FIIs/FPIs can invest in the Security Receipts (SRs) issued by ARCs registered with Reserve Bank. FIIs/FPIs can invest up to 74 per cent of each tranche of scheme of SRs. Such investment should be within the FII/FPI limit on corporate bonds prescribed from time to time, and sectoral caps under extant FDI Regulations should also be complied with.</p> <p>(v) All investments would be subject to provisions of section 3(3)(f) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.</p>		
F.2	Banking - Private sector		
F.2.1	Banking - Private sector	74%	Automatic upto 49% Government route beyond 49% and upto 74%
F.2.2	<p>Other conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) This 74% limit will include investment under the Portfolio Investment Scheme (PIS) by FIIs/FPIs, NRIs and shares acquired prior to September 16, 2003 by erstwhile OCBs, and shall continue to include investment made by non-residents under IPOs, Private placements, DRs and through acquisition of shares from existing shareholders. 2) The aggregate foreign investment in a private bank from all sources will be allowed - up to a maximum of 74 per cent of the paid-up capital of the Bank. At all times, at least 26 per cent of the paid up capital will have to be held by residents, except in regard to a wholly-owned subsidiary of a foreign bank. 3) The stipulations as above will be applicable to all investments in existing private sector banks also. 4) The permissible limits under portfolio investment schemes through stock exchanges for FIIs/FPIs and NRIs will be as follows: <ol style="list-style-type: none"> (i) In the case of FIIs/FPIs, as hitherto, individual FII/FPI holding is restricted to below 10 per cent of the total paid-up capital, aggregate limit for all FIIs/FPIs/QFIs cannot exceed 24 per cent of the total paid-up capital, which can be raised up to sectoral limit of 74 per cent of the total paid-up capital by the bank concerned through a resolution by its Board of Directors followed by a special resolution to that effect by its General Body. <ol style="list-style-type: none"> a. In the case of NRIs, as hitherto, individual holding is restricted to 5 per cent of the total paid-up capital both on repatriation and non-repatriation basis and aggregate limit cannot exceed 10 per cent of the total paid-up capital both on repatriation and non-repatriation basis. However, NRI holding can be allowed up to 24 per cent of the total paid-up capital both on repatriation and non- repatriation basis provided the banking company passes a special resolution to that effect in the General Body. b. Applications for foreign direct investment in private banks having joint venture/subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank of India (RBI) for consideration in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) in order to ensure that the 49 per cent limit of foreign shareholding applicable for the insurance sector is not being breached. c. Transfer of shares under FDI from residents to non-residents will continue to require approval of RBI and Government as per Regulation 14 (5) as applicable. d. The policies and procedures prescribed from time to time by RBI and other institutions such as SEBI, Ministry of Corporate Affairs and IRDAI on these matters will continue to apply. e. RBI guidelines relating to acquisition by purchase or otherwise of shares of a private bank, if such acquisition results in any person owning or controlling 5 per cent or more of the paid up capital of the private bank will apply to non- resident investors as well. 		

	<p>(ii) Setting up of a subsidiary by foreign banks</p> <p>(a) Foreign banks will be permitted to either have branches or subsidiaries but not both.</p> <p>(b) Foreign banks regulated by banking supervisory authority in the home country and meeting Reserve Bank's licensing criteria will be allowed to hold 100 per cent paid-up capital to enable them to set up a wholly-owned subsidiary in India.</p> <p>(c) A foreign bank may operate in India through only one of the three channels viz., (i) branches (ii) a wholly-owned subsidiary and (iii) a subsidiary with aggregate foreign investment up to a maximum of 74 per cent in a private bank.</p> <p>(d) A foreign bank will be permitted to establish a wholly-owned subsidiary either through conversion of existing branches into a subsidiary or through a fresh banking license. A foreign bank will be permitted to establish a subsidiary through acquisition of shares of an existing private sector bank provided at least 26 per cent of the paid-up capital of the private sector bank is held by residents at all times consistent with para (i) (b) above.</p> <p>(e) A subsidiary of a foreign bank will be subject to the licensing requirements and conditions broadly consistent with those for new private sector banks.</p> <p>(f) Guidelines for setting up a wholly-owned subsidiary of a foreign bank will be issued separately by RBI.</p> <p>(g) All applications by a foreign bank for setting up a subsidiary or for conversion of their existing branches to subsidiary in India will have to be made to the RBI.</p> <p>(iii) At present there is a limit of ten per cent on voting rights in respect of banking companies, and this should be noted by potential investor. Any change in the ceiling can be brought about only after final policy decisions and appropriate Parliamentary approvals.</p>		
F.3	Banking - Public Sector		
F.3.1	Banking - Public Sector subject to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Acts, 1970/80. This ceiling (20%) is also applicable to the State Bank of India and its associate banks.	20%	Government
F.4	Commodity Exchanges		
F.4.1	<p>1. Futures trading in commodities are regulated under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. Commodity Exchanges, like Stock Exchanges, are infrastructure companies in the commodity futures market. With a view to infuse globally acceptable best practices, modern management skills and latest technology, it was decided to allow foreign investment in Commodity Exchanges.</p> <p>2. For the purposes of this Chapter,</p> <p>(i) "Commodity Exchange" is a recognized association under the provisions of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, as amended from time to time, to provide exchange platform for trading in forward contracts in commodities.</p> <p>(ii) "Recognized association" means an association to which recognition for the time being has been granted by the Central Government under section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952.</p> <p>(iii) "Association" means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purposes of regulating and controlling the business of the sale or purchase of any goods and commodity derivative.</p> <p>(iv) "Forward contract" means a contract for the delivery of goods and which is not a ready delivery contract.</p> <p>(v) "Commodity derivative" means-</p> <ul style="list-style-type: none"> • a contract for delivery of goods, which is not a ready delivery contract; or • a contract for differences which derives its value from prices or indices of prices of such underlying goods or activities, services, rights, interests and events, as may be notified in consultation with the SEBI by the Central Government, but does not include securities. 		
F.4.2	Commodity Exchange	49%	Automatic
F.4.3	<p>Other conditions:</p> <p>(i) FII/FPI purchases shall be restricted to secondary market only.</p> <p>(ii) No non-resident investor/entity, including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies.</p> <p>(iii) Foreign investment in commodity exchanges will be subject to the guidelines of the Central Government / SEBI from time to time.</p>		
F.5	Credit Information Companies (CIC)		
F.5.1	Credit Information Companies	100 %	Automatic
F.5.2	Other Conditions:		
	(1) Foreign investment in Credit Information Companies is subject to the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.		

	<p>(2) Foreign investment is permitted subject to regulatory clearance from RBI.</p> <p>(3) Such FII/FPI investment would be permitted subject to the conditions that:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) A single entity should directly or indirectly hold below 10% equity; (b) Any acquisition in excess of 1 % will have to be reported to RBI as a mandatory requirement; and (c) FIIs investing in CICs shall not seek a representation on the Board of Directors based upon their shareholding. 		
F.6	Infrastructure Company in the Securities Market		
F.6.1	Infrastructure companies in Securities Markets, namely, stock exchanges, depositories and clearing corporations, in compliance with SEBI Regulations	49%	Automatic
F.6.2	Other Conditions:		
F.6.2.1	FII/FPI can invest only through purchases in the secondary market		
F.7.	Insurance		
F.7.1	Insurance <ul style="list-style-type: none"> (i) Insurance Company (ii) Insurance Brokers (iii) Third Party Administrators (iv) Surveyors and Loss Assessors (v) Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) 	49%	Automatic upto 26%;; Government route beyond 26% and upto 49%
F.7.2	<p>Other Conditions:</p> <p>(a) No Indian insurance company shall allow the aggregate holdings by way of total foreign investment in its equity shares by foreign investors, including portfolio investors, to exceed forty-nine percent of the paid up equity capital of such Indian insurance company.</p> <p>(b) Foreign direct investment proposals which take the total foreign investment in the Indian insurance company above 26 percent and up to the cap of 49 percent shall be under Government route.</p> <p>(c) Foreign investment in the sector is subject to compliance of the provisions of the Insurance Act, 1938 and the condition that Companies bringing in FDI shall obtain necessary license from the Insurance Regulatory & Development Authority of India for undertaking insurance activities.</p> <p>(d) An Indian insurance company shall ensure that its ownership and control remains at all times in the hands of resident Indian entities as determined/notified by Department of Financial Services.</p> <p>(e) Foreign portfolio investment in an Indian insurance company shall be governed by the provisions contained in sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation 5 of FEMA Regulations, 2000 and provisions of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations.</p> <p>(f) Any increase of foreign investment of an Indian insurance company shall be in accordance with the pricing guidelines specified by Reserve Bank of India under the FEMA.</p> <p>(g) The foreign equity investment cap of 49 percent shall apply on the same terms as above to Insurance Brokers, Third Party Administrators, Surveyors and Loss Assessors and Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).</p> <p>(h) Provided that where an entity like a bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from their primary (i.e. non-insurance related) business must remain above 50 percent of their total revenues in any financial year.</p> <p>(i) The provisions of paragraphs F.2.2 (3) (i) (c) & (e), relating to 'Banking-Private Sector', shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies.</p> <p>(j) Terms 'Control', 'Equity Share Capital', 'Foreign Direct Investment' (FDI), 'Foreign Investors', 'Foreign Portfolio Investment', 'Indian Insurance Company', 'Indian Company', 'Indian Control of an Indian Insurance Company', 'Indian Ownership', 'Non-resident Entity', 'Public Financial Institution', 'Resident Indian Citizen', 'Total Foreign Investment' will have the same meaning as provided in Notification No. G.S.R 115 (E), dated 19th February, 2015.</p>		

F.8.	Non-Banking Finance Companies (NBFCs)		
F.8.1	Foreign investment in NBFC is allowed under the automatic route in only the following activities: (i) Merchant Banking (ii) Underwriting (iii) Portfolio Management Services (iv) Investment Advisory Services (v) Financial Consultancy (vi) Stock Broking (vii) Asset Management (viii) Venture Capital (ix) Custodian Services (x) Factoring (xi) Credit Rating Agencies (xii) Leasing & Finance (xiii) Housing Finance (xiv) Forex Broking (xv) Credit Card Business (xvi) Money Changing Business (xvii) Micro Credit (xviii) Rural Credit	100%	Automatic
F.8.2	Other Conditions		
	<p>(1) Investment would be subject to the following minimum capitalisation norms:</p> <p>(i) US \$0.5 million for foreign capital up to 51% to be brought upfront.</p> <p>(ii) US \$ 5 million for foreign capital more than 51% and up to 75% to be brought upfront.</p> <p>(iii) US \$ 50 million for foreign capital more than 75% out of which US \$ 7.5 million to be brought upfront and the balance in 24 months.</p> <p>(iv) NBFCs (i) having foreign investment more than 75% and up to 100%, and (ii) with a minimum capitalisation of US\$ 50 million, can set up step down subsidiaries for specific NBFC activities, without any restriction on the number of operating subsidiaries and without bringing in additional capital. The minimum capitalization condition as mandated by para 3.10.4.1 of DIPP Circular 1 on Consolidated FDI Policy, therefore, shall not apply to downstream subsidiaries.</p> <p>(v) Joint Venture operating NBFCs that have 75% or less than 75% foreign investment can also set up subsidiaries for undertaking other NBFC activities, subject to the subsidiaries also complying with the applicable minimum capitalisation norm mentioned in (i), (ii) and (iii) above and (vi) below.</p> <p>(vi) Non-Fund based activities: US\$ 0.5 million to be brought upfront for all permitted non-fund based NBFCs irrespective of the level of foreign investment subject to the following condition: It would not be permissible for such a company to set up any subsidiary for any other activity, nor it can participate in any equity of an NBFC holding/operating company.</p> <p>Note: The following activities would be classified as Non-Fund Based activities:</p> <p>(a) Investment Advisory Services (b) Financial Consultancy (c) Forex Broking (d) Money Changing Business (e) Credit Rating Agencies</p> <p>(vii) This will be subject to compliance with the guidelines of RBI.</p> <p>Note: (i) Credit Card business includes issuance, sales, marketing & design of various payment products such as credit cards, charge cards, debit cards, stored value cards, smart card, value added cards etc.</p> <p>(ii) Leasing & Finance covers only financial leases and not operating leases.</p> <p>FDI in operating leases is permitted up to 100% on the automatic route.</p> <p>(2) The NBFC will have to comply with the guidelines of the relevant regulator/s, as applicable.</p>		
F.8.3	White Label ATM Operations	100%	Automatic
	<p>Other Conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> Any non-bank entity intending to set up a WLAs should have a minimum net worth of Rs. 100 crore as per the latest financial year's audited balance sheet, which is to be maintained at all times. In case the entity is also engaged in any other 18 NBFC activities, then the foreign investment in the company setting up WLA, shall have to comply with the minimum capitalisation norms for foreign investment in NBFC activities, as provided in para F.8.2. FDI in the WLAs will be subject to the specific criteria and guidelines issued by RBI vide Circular No. DPSS.CO.PD.No.2298/02.10.002/2011-12, as amended from time to time. 		

F.9	Power Exchanges			
F.9.1	Power Exchanges under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010	49%	Automatic	
F.9.2	Other conditions			
	(i) FII purchases shall be restricted to secondary market only; (ii) No non-resident investor/entity, including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies; and (iii) The foreign investment would be in compliance with SEBI Regulations; other applicable laws/regulations; security and other conditionalities.			
F.10	Pension Sector	49%	Automatic up to 26%; Government route beyond 26% and up to 49 %	
17.	Pharmaceuticals			
17.1	Greenfield	100%	Automatic	
17.2	Brown Field	100%	Government	
17.3	Other Conditions	<p>(i) 'Non-compete' clause would not be allowed except in special circumstances with the approval of the Foreign Investment Promotion Board.</p> <p>(ii) The prospective investor and the prospective investee are required to provide a certificate along with the FIPB application.</p> <p>(iii) Government may incorporate appropriate conditions for FDI in brownfield cases, at the time of granting approval.</p> <p>Note :</p> <p>i. FDI upto 100% under the automatic route is permitted for manufacturing of medical devices. The abovementioned conditions will, therefore, not be applicable to greenfield as well as brownfield projects of this industry.</p> <p>ii. Medical device means :-</p> <p>a) Any instrument, apparatus, appliance, implant, material or other article, whether used alone or in combination, including the software, intended by its manufacturer to be used specially for human beings or animals for one or more of the specific purposes of :-</p> <p>(aa) Diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of any disease or disorder;</p> <p>(ab) diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of, or assistance for, any injury or handicap;</p> <p>(ac) investigation, replacement or modification or support of the anatomy or of a physiological process;</p> <p>(ad) supporting or sustaining life;</p> <p>(ae) disinfection of medical devices;</p> <p>(af) control of conception;</p> <p>and which does not achieve its primary intended action in or on the human body or animals by any pharmacological or immunological or metabolic means, but which may be assisted in its intended function by such means;</p> <p>b) an accessory to such an instrument, apparatus, appliance, material or other article;</p> <p>c) a device which is reagent, reagent product, calibrator, control material, kit, instrument, apparatus, equipment or system whether used alone or in combination thereof intended to be used for examination and providing information for medical or diagnostic purposes by means of in vitro examination of specimens derived from the human body or animals.</p> <p>iii. The definition of medical device at Note (ii) above would be subject to the amendment in Drugs and Cosmetics Act.</p>		
18	Railway Infrastructure			
	Construction, operation and maintenance of the following: (i) Suburban corridor projects through PPP, (ii) speed train projects, (iii) Dedicated freight lines, (iv) Rolling stock including train sets, and locomotives/coaches manufacturing and maintenance facilities, (v) Railway Electrification, (vi) Signaling systems, (vii) Freight	100%	Automatic	

	terminals, (viii) Passenger terminals, (ix) Infrastructure in industrial park pertaining to railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to main railway line and (x) Mass Rapid Transport Systems.		
	<p>Note:-</p> <p>(i) Foreign Direct Investment in the abovementioned activities open to private participation including FDI is subject to sectoral guidelines of Ministry of Railways.</p> <p>(ii) Proposals involving FDI beyond 49% in sensitive areas from security point of view, will be brought by the Ministry of Railways before the Cabinet Committee on Security (CCS) for consideration on a case to case basis.</p>		

D. In Schedule 9,

(i) the existing paragraph 4 shall be amended as under, namely:

“4. Entry Route

FDI in LLPs is permitted, subject to the following conditions:

- i. *FDI is permitted under the automatic route in LLPs operating in sectors/activities where 100% FDI is allowed through the automatic route and there are no FDI linked performance conditions.*
- ii. *An Indian company or an LLP, having foreign investment, will be permitted to make downstream investment in another company or LLP engaged in sectors in which 100% FDI is allowed under the automatic route and there are no FDI-linked performance conditions. Onus shall be on the Indian company/ LLP accepting downstream investment to ensure compliance with the above conditions.*
- iii. *FDI in LLP is subject to the compliance of the conditions of LLP Act, 2008.”*

(ii) the existing paragraph 8 shall stands deleted.

E. The existing Schedule 11 shall be substituted by the following, namely:

“Schedule 11

[See Regulation 5(10)]

Investment by a person resident outside India in an Investment Vehicle

1. A person resident outside India including an RFPI and an NRI may invest in units of Investment Vehicles subject to the conditions laid down in this Schedule.
2. The payment for the units of an Investment Vehicle acquired by a person resident or registered / incorporated outside India shall be made by an inward remittance through the normal banking channel including by debit to an NRE or an FCNR account.
3. A person resident outside India who has acquired or purchased units in accordance with this Schedule may sell or transfer in any manner or redeem the units as per regulations framed by SEBI or directions issued by RBI.
4. Downstream investment by an Investment Vehicle shall be regarded as foreign investment if either the Sponsor or the Manager or the Investment Manager is not Indian ‘owned and controlled’ as defined in Regulation 14 of the principal Regulations.

Provided that for sponsors or managers or investment managers organized in a form other than companies or LLPs, SEBI shall determine whether the sponsor or manager or investment manager is foreign owned and controlled.

Explanation 1: Ownership and control is clearly determined as per the extant FDI policy. AIF is a pooled investment vehicle. ‘Control’ of the AIF should be in the hands of ‘sponsors’ and ‘managers/investment managers’, with the general exclusion to others. In case the ‘sponsors and ‘managers/investment managers’ of the AIF are individuals, for the treatment of downstream investment by such AIF as domestic, ‘sponsors’ and ‘managers/investment managers’ should be resident Indian citizens.

Explanation 2: The extent of foreign investment in the corpus of the Investment Vehicle will not be a factor to determine as to whether downstream investment of the Investment Vehicle concerned is foreign investment or not.

5. Downstream investment by an Investment Vehicle that is reckoned as foreign investment shall have to conform to the sectoral caps and conditions / restrictions, if any, as applicable to the company in which the downstream investment is made as per the FDI Policy or Schedule 1 of the principal Regulations.

6. Downstream investment in an LLP by an Investment Vehicle that is reckoned as foreign investment has to conform to the provisions of Schedule 9 of the principal Regulations as well as the extant FDI policy for foreign investment in LLPs.

7. An Alternative Investment Fund Category III with foreign investment shall make portfolio investment in only those securities or instruments in which a Registered Foreign Portfolio Investor is allowed to invest under the principal Regulations.

8. The Investment Vehicle receiving foreign investment shall be required to make such report and in such format to Reserve Bank of India or to SEBI as may be prescribed by them from time to time.”

[No. 1/1/EM/2016]

B.P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
	G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013

G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013	G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013	G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013	G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013	G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013	G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013	G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013	G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014	G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014	G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014	G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014	G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014	G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014	G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015
G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014	G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015
G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014	G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015
G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014	
G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014	